www.deshkiupasana.com

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - UPHIN/2022/86937

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

DKU LIVE

सब पर नज़र, सबकी ख़बर

वर्ष – 04 | अंक – 103 | जौनपुर बुधवार, 26 नवम्बर 2025 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

हिमंत बिस्वा सरमा का दावा, यह सुनियोजित हत्या है

असम, (एजेंसी)। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शीतकालीन विधानसभा सत्र में कहा कि उन्होंने जुबीन गर्ग की मौत के मामले में स्थगन प्रस्ताव का कभी विरोध नहीं किया और इस बात पर जोर दिया कि प्रारंभिक जाँच के अनुसार, गर्ग की मौत गैर इरादतन हत्या का मामला नहीं, बल्कि एक साफ–सुथरी हत्या थी। विपक्ष के प्रश्न का उत्तर देते हुए, असम के मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि उन्होंने अदालत से बीएनएस की धारा 61, 105 और 106 के साथ धारा 103 को भी शामिल करने का अनुरोध किया था। चर्चा के बाद, अदालत ने उनकी याचिका स्वीकार कर ली और धारा 103 को जोड़ने की अनुमति दे दी। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह पहले दिन से ही एक हत्या का मामला रहा है और धारा 103 को शामिल किए बिना, सभी अभियुक्तों को जमानत मिल सकती थी। हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि आज हमने जुबीन गर्ग के सम्मान में स्थगन प्रस्ताव का विरोध नहीं किया है, हम इसका समर्थन करते हैं। जुबीन गर्ग की मृत्यु 19 सितंबर, 2025 को हुई और अगले दिन 20 सितंबर को हमने पहली एफआईआर दर्ज की। पहले दिन हमें संदेह था कि जुबीन गर्ग की मृत्यु स्वाभाविक मौत नहीं है। हमने 20 सितंबर, 2025 को बीएनएस की धारा 61, 105, 106 के तहत एफआईआर दर्ज की

लोकतंत्र की रक्षा के लिए कांग्रेस का आह्वान

नई दिल्ली, (एजेंसी)। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 26 नवंबर को संविधान दिवस को श्संविधान बचाओ दिवसश के रूप में मनाएगी, जिसका उद्देश्य लोकतांत्रिक संस्थाओं और संविधान की मूल भावना के समक्ष मौजूदा चुनौतियों को उजागर करना है। यह पहल देश में संवैधानिक नैतिकता और लोकतंत्र पर बढ़ते खतरों, जैसे चुनावी कदाचार और संस्थाओं के दुरुपयोग, के प्रति कांग्रेस की चिंता को दर्शाती है। पार्टी ने सभी राज्य इकाइयों को सेमिनार और संगोष्ठियों जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को इन खतरों से अवगत कराने और संविधान की रक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करने का निर्देश दिया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सभी राज्य इकाइयों को निर्देश दिया है कि वे 26 नवंबर को देश भर के प्रदेश कांग्रेस समितियों (पीसीसी) कार्यालयों और जिला मुख्यालयों में श्संविधान बचाओ दिवसश के रूप में मनाएँ। पत्र में, कांग्रेस ने इस अवसर के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संविधान दिवस के पावन अवसर पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सभी प्रदेश कांग्रेस समितियों से आह्वान करती है कि वे 26 नवंबर को देश भर में संविधान बचाओ दिवस के रूप में मनाएँ। हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं और हमारे संविधान की मूल भावना के समक्ष अभूतपूर्व चुनौतियों को देखते हुए इस वर्ष का यह दिवस अत्यंत महत्वपूर्ण है।

राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण 'एक नए युग की शुरुआत' है : योगी आदित्यनाथ

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण को "एक नए युग की शुरुआत" बताया। उन्होंने इस कार्यक्रम में मौजूद रहने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक मोहन भागवत तथा उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का धन्यवाद किया। आगंतुकों को संबोधित करते हुए, आदित्यनाथ ने कहा कि भगवान राम का भव्य मंदिर 140 करोड़ भारतीयों की "आस्था, सम्मान और आत्म–गौरव" का प्रतीक है। उन्होंने इसके निर्माण में योगदान देने वाले सभी "कर्मयोगियों" का दिल से आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह दिन "उन संतों, योद्धाओं और राम भक्तों की "अटूट भक्ति" को

समर्पित है जिन्होंने इस आंदोलन और लंबे संघर्ष के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, जिसका नतीजा मंदिर के निर्माण के रूप में सामने आया।" आदित्यनाथ ने कहा कि जब 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में मोदी ने देश का नेतृत्व संभाला था, तो लाखों लोगों के दिलों में "संकल्प और विश्वास का सूरज" जगा। उन्होंने कहा, "आज, वह संकल्प इस भव्य राम मंदिर के रूप में सभी भारतीयों और भक्तों के सामने पूरा हुआ है।" उन्होंने कहा कि राम मंदिर के ऊपर फहरा रहा ध्वज सच्चाई, न्याय, गरिमा और राष्ट्रीय धर्म का प्रतीक है। आदित्यनाथ ने कहा, "यह एक विकसित भारत के दृष्टिकोण को भी दिखाता है, क्योंकि संकल्प का कोई विकल्प नहीं है, और पिछले 11 सालों में हम सभी ने एक बदलते भारत को देखा है। हम एक ऐसा भारत देख रहे हैं जहां विरासत और विकास पूरे तालमेल के साथ मौजूद हैं, जो देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं।" उन्होंने राम मंदिर आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि अटूट विश्वास बना रहा।

प्रधानमंत्री मोदी ने गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की

नई दिल्ली, (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को गुरु तेग बहादुर को उनके 350वें शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर हम उनके अद्वितीय साहस और बलिदान को नमन करते हैं।'' उन्होंने कहा, ''आस्था और मानवता की रक्षा के लिए उनकी शहादत हमारे समाज को सदैव आलोकित करेगी।'' एक अप्रैल, 1621 को अमृतसर के गुरु के महल में जन्मे तेग बहादुर, गुरु हरगोबिंद के सबसे छोटे पुत्र और नौवें सिख गुरु थे। 24 नवंबर, 1675 को दिल्ली में मुगल बादशाह औरंगजेब के आदेश पर उनका सिर कलम कर दिया गया था। इससे पहले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सोमवार को नौवें सिख गुरु, गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उन्होंने अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर

करने में संकोच नहीं किया। शाह ने यहां लाल किले में नौवें सिख गुरु की 350वीं शहीदी दिवस के उपलक्ष्य दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित एक समारोह में हिस्सा लिया। लाल किले के नजदीक 10 नवंबर को हुए विस्फोट के बाद 17वीं सदी के इस स्मारक पर यह पहला बड़ा कार्यक्रम था। इस विस्फोट में 15 लोगों की जान चली गई थी। केंद्रीय गृह मंत्री ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "गुरु तेग बहादुर जी ने अन्याय और अधर्म का जिस साहस और शौर्य के साथ सामना किया, वह हर भारतीय के लिए प्रेरणा का केंद्र है। धर्म की रक्षा के लिए वे अपने प्राणों को आहूत करने से भी पीछे नहीं हटे। उनका जीवन भारत की आध्यात्मिक चेतना, साहस और बलिदान की अमर गाथा है।

अमित शाह का गुरु तेग बहादुर को नमन

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस पर मंगलवार को उन्हें श्रद्धांजलि दी और कहा कि नौवें सिख गुरु ने आध्यात्मिक साधना की, दिव्य समागम आयोजित किए और क्रूर आक्रमणकारियों से स्वसंस्कृति और स्वधर्म की रक्षा की। शाह ने 'एक्स' पर एक संदेश में कहा, ''सिख धर्म के नौवें गुरु, 'हिंद की चादर' गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस पर उन्हें नमन करता हूं।''

गृह मंत्री ने कहा, ''गुरु तेग बहादुर जी ने एक ही जीवनकाल में आध्यात्मिक साधना भी की, सत्संग भी किए और क्रूर आक्रांताओं से स्वसंस्कृति व स्वधर्म की रक्षा भी की। उन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए संघर्ष किया, अत्याचारी मुगल को चुनौती दी और धर्म की खातिर अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया।'' शाह ने कहा, ''शौर्य, संयम, त्याग और समर्पण से भरी गुरु साहिब जी की बलिदान गाथा को याद कर आज भी मन गौरव और राष्ट्ररक्षा के संकल्प से भर जाता है। इससे पहले सोमवार को पंजाब में गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहादत की सालगिरह के मौके पर आनंदपुर साहिब के आसमान में 500 ड्रोन का शानदार शो हुआ। मुख्यमंत्री भगवंत मान और ।।च के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल इस इवेंट में शामिल हुए, जिसमें नौवें सिख गुरु के जीवन, सोच और शहादत को दिखाया गया। मान ने इसे उत्तर भारत में "हिंद की चादर" को समर्पित पहली इतनी बड़ी ड्रोन श्रद्धांजलि बताया। तीन दिन के इस यादगार कार्यक्रम के तहत, पंजाब विधानसभा ने आनंदपुर साहिब के भाई जैता जी मेमोरियल पार्क में एक स्पेशल सेशन बुलाया। यह पहली बार था जब विधानसभा ने राज्य की राजधानी के बाहर कोई काम किया।

सीएम नीतीश का बड़ा ऐलान, 1 करोड़ युवाओं को नौकरी

बिहार, (एजेंसी)। बिहार को विकसित राज्य बनाने की दिशा में काम तेजी से शुरू हो गया है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स पर बड़ी जानकारी दी है। नीतीश ने नई सरकार के गठन के बाद आज एक्स पर लिखा कि राज्य में अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार मिले, ये शुरू से ही हमलोगों की प्राथमिकता रही है। सात निश्चय–2 के तहत वर्ष 2020–25 के बीच राज्य में 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार दिया गया है। अगले 5 वर्षों (2025–30) में हमलोगों ने 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। नीतीश ने आगे लिखा कि नई सरकार के गठन के पश्चात् राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने एवं अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करने के लिए हमलोगों ने तेजी से काम शुरू कर दिया है। बदलते बिहार के विकास की गति को बल देने हेतु बिहार में प्रौद्योगिकी और सेवा आधारित नवाचारों की न्यू ऐज इकोनॉमी के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु इस क्षेत्र की बिहार से संबंध रखनेवाले अग्रणी उद्यमियों के सुझाव प्राप्त कर योजनाओं एवं नीतियों का निर्धारण किया जाएगा। साथ ही बिहार को एक 'वैश्विक–टंबा मदक–भ्नइ' एवं 'ग्लोबल वर्क प्लेस' के रूप में विकसित एवं स्थापित करने हेतु महत्वपूर्ण विभागों तथा प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों एवं विशेषज्ञों के सहयोग से एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि बिहार की जनसंख्या में युवाओं की भागीदारी काफी अधिक है। इसको सार्थक दिशा देने पर बिहार देश का सबसे तेजी से विकास करने वाला राज्य बन सकता है। बिहार के बड़ी

संख्या में उपलब्ध युवा मानव संसाधन को ध्यान में रखते हुए बिहार को पूर्वी भारत के नए टेक्नोलॉजी हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए बिहार में डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, मेगा टेक सिटी व फिनटेक सिटी की स्थापना की जाएगी एवं उद्योगों का जाल बिछाने हेतु वृहद कार्ययोजना तैयार कर योजनाओं को क्रियान्वित किया जाएगा। 10वीं बार सीएम पर दी शपथ लेने के बाद उन्होंने कहा कि राज्य में नई चीनी मिलों की स्थापना एवं पुरानी बंद पड़ी चीनी मिलों को पुनः चालू करने हेतु नीति एवं कार्ययोजना बनाई गई है।

कर्नाटक में सीएम पद पर सियासत, सिद्धारमैया के बाद डीके शिवकुमार ने भी की खरगे से मुलाकात

बंगलूरू, (एजेंसी)। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर जारी रस्साकशी जारी है। ऐसे में इस बात को लेकर चर्चा तेज जब हो गई जब सिद्धारमैया की मुलाकात के बाद आज यानी मंगलवार को उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने भी बंगलूरू में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक, शिवकुमार की मुलाकात ऐसे समय में हुई जब पार्टी अध्यक्ष खरगे दिल्ली जाने के लिए तैयार थे, तभी उपमुख्यमंत्री शिवकुमार उनसे मिलने पहुंचे। इसके बाद मुलाकात के बाद, दोनों ने एक ही कार में बैठकर एयरपोर्ट की ओर रवाना हुए। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर अटकलें तेज तब हो गई

जब राज्य की कांग्रेस सरकार ने 20 नवंबर को अपने पांच साल के कार्यकाल का आधा समय पूरा किया। इसी बीच, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और शिवकुमार के बीच कथित 'पावर शेयरिंग' समझौते की बातें भी सामने आई हैं। ऐसे में चर्चा तेज हो गई कि क्या अब डीके शिवकुमार को अगले ढाई साल के लिए मुख्यमंत्री पद दिया जा सकता है। सोमवार को खरगे से मुलाकात के बाद सिद्धारमैया ने अपना रुख साफ किया था कि वे कांग्रेस हाई कमान के फैसले के आधार पर चलेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हम हाई कमान के फैसले का पालन करेंगे। जो भी निर्णय लिया जाएगा, मुझे उसे स्वीकार करना होगा। शिवकुमार को भी यही करना चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि क्या शिवकुमार अगला मुख्यमंत्री होंगे, तो उन्होंने दोहराया कि यह फैसला हाई कमान करेगी। कुछ महीने पहले हाई कमान ने कैबिनेट फेरबदल की मंजूरी दी थी, लेकिन सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि सरकार 2.5 साल पूरा करे, उसके बाद बदलाव होगा। अब उन्होंने कहा कि हाई कमान जो फैसला करेगी, वही मान्य होगा। ऐसे में पिछले हफ्ते कुछ डीके शिवकुमार के समर्थक विधायक दिल्ली गए और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से मिले। इसके बाद सिद्धारमैया ने खरगे से बेंगलुरु में एक घंटे से ज्यादा लंबी बैठक की। सूत्रों की माने तो सीएम सिद्धारमैया कैबिनेट में फेरबदल चाहते हैं, जबकि शिवकुमार चाहते हैं कि पहले मुख्यमंत्री पद पर फैसला हो।

भगवद् गीता धार्मिक सीमाओं से परे, धार्मिक जीवन जीने के लिए सार्वभौमिक मार्गदर्शक है : जयशंकर

नई दिल्ली, (एजेंसी)। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव में कहा कि श्रीमद् भगवद् गीता धार्मिक सीमाओं से परे है और यह धार्मिक जीवन, आंतरिक शक्ति और आध्यात्मिक स्पष्टता के लिए एक सार्वभौमिक मार्गदर्शक है। जयशंकर ने यह बात एक वीडियो संदेश में कही, जिसे सोमवार को कुरुक्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव में प्रसारित किया गया। यह महोत्सव 15 नवंबर को शुरू हुआ था और पांच दिसंबर को समाप्त होगा। उन्होंने कहा, ''यह पवित्र ग्रंथ धार्मिक सीमाओं से परे है। यह धार्मिक जीवन, आंतरिक शक्ति और आध्यात्मिक स्पष्टता के लिए एक सार्वभौमिक मार्गदर्शक है।'' विदेश मंत्री ने कहा, ''इसकी शिक्षाएं विभिन्न पीढ़ियों और भौगोलिक क्षेत्रों के लोगों के मन को प्रभावित करती रहती हैं, बदलती दुनिया में मार्गदर्शन और ज्ञान प्रदान करती हैं।" रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा 10वें अंतरराष्ट्रीय गीता सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद विदेश मंत्री का वीडियो संदेश प्रसारित किया गया। यह सम्मेलन तीन सप्ताह के महोत्सव के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया था। यह कार्यक्रम कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, विदेश मंत्रालय और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था, और इसमें आध्यात्मिक नेताओं, विद्वानों, हरियाणा के कई कैबिनेट मंत्रियों, सांसद नवीन जिंदल और गीता मर्मज्ञ स्वामी ज्ञानानंद महाराज सहित अन्य लोगों ने भाग लिया।

संविधान पूरी तरह से लागू हो जाए, तो रामभद्राचार्य जेल में होंगे : उदित राज

नई दिल्ली, (एजेंसी)। जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने देश से श्जातिगत व्यवस्थाश को खत्म करने की वकालत की है, लेकिन इस पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। उदित राज का कहना है कि अगर आज संविधान पूरी तरह से लागू हो जाए, तो रामभद्राचार्य जेल के अंदर होंगे। जगद्गुरु रामभद्राचार्य से जुड़े सवाल पर कांग्रेस नेता उदित राज ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, संविधान ही जगद्गुरु रामभद्राचार्य का इलाज है। अगर आज संविधान पूरी तरह से लागू हो जाए, तो रामभद्राचार्य जेल के अंदर होंगे। इस पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि रामभद्राचार्य को केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी के सामने अपने विचार रखने चाहिए। उन्होंने कहा, ष्दो–तिहाई बहुमत से जीतकर संसद में आओ और सरकार बनाकर कानून बदल लें या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी आपकी बात सुनेंगे, क्योंकि आप उनके ग्रुप का हिस्सा हैं, फिर आप अपने मंत्रियों से रिजर्वेशन हटाने के लिए कह सकते हैं?ष कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने भी रामभद्राचार्य की टिप्पणी पर जवाब दिया। उन्होंने कहा, ष्मैं शंकराचार्य से अनुरोध करूंगा कि शंकराचार्यों में दलित, एससी और एसटी को शामिल करें और फिर आरक्षण को खत्म करें।ष पप्पू यादव ने यह भी कहा कि ऐसे लोगों (रामभद्राचार्य) का इलाज अंबेडकरवादी विचारों से होगा। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा, राम भद्राचार्य जैसे लोगों के ऐसे बयान निंदनीय हैं। धार्मिक लोगों को राजनीति में दखल नहीं देना चाहिए। जो लोग भारत की सनातन संस्कृति को खत्म करने पर तुले हुए हैं।

मुझे हराने का दम नहीं, चुनाव आयोग अब बीजेपी कमीशन : ममता बनर्जी

कोलकाता, (एजेंसी)। विधानसभा चुनाव अभी कुछ महीने दूर हैं। उससे पहले बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सियासत गरमा गई है। इसी माहौल में मंगलवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बोंगांव में एक सभा की। एसआईआर विरोधी रैली में ममता ने कहा कि भाजपा राजनीतिक रूप से मेरा मुकाबला नहीं कर सकती और न ही मुझे हरा सकती है। उन्होंने कहा कि 'इलेक्शन कमीशन' अब एक निष्पक्ष संस्था नहीं रह गई है, यह 'बीजेपी कमीशन' बन गई है। बनर्जी ने सवाल किया कि क्या भाजपा शासित राज्यों में एसआईआर का आयोजन यह दर्शाता है कि केंद्र

सरकार स्वीकार करती है कि वहां श्घुसपैठियाश मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि मैं बीरभूम में पैदा हुई, वरना मुझे भी बांग्लादेशी कहते। अपने भाषण की शुरुआत में ममता ने हेलीकॉप्टर को लेकर भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा, ष्मैं हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल नहीं करती। मैं कार से चलती हूँ। राज्य सरकार के पास एक हेलीकॉप्टर है। यह किराए पर है। मुझे सुबह 10 बजे यहाँ आना था। सुबह अचानक पता चला कि हेलीकॉप्टर नहीं जाएगा। चुनाव से पहले ही झगड़ा शुरू हो गया था। लेकिन मेरे लिए यह अच्छा रहा। रास्ते में कई जगह घूमा। लोगों से बातें कीं। उन्होंने दावा किया कि मैंने भाजपा से कहा कि मैं जो खेल खेलूँगी, उसमें मुझे कोई छू नहीं सकता। गलियों में घूमने से मेरा संपर्क और भी लोगों से हुआ है। एसआईआर के बारे में उन्होंने कहा कि एसआईआर कराने में तीन साल लगते हैं। 2002 में भी यही हुआ था। हमने कहा था कि कोई भी वैध मतदाता छूटेगा नहीं। अब नियम बदल रहे हैं। आयोग तय कर रहा है कि सरकार में कौन बैठेगा। चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए। पहले मुझे आधार कार्ड मिला था। वहाँ सबने पैसे खर्च किए। मुझे भी पैसे खर्च करने पड़े। मेरा आधा घंटा बर्बाद हो गया।

संपादकीय

आरक्षण के लाभ से वंचित

पिछले साल दिए एक निर्णय में जस्टिस गवई ने कहा था कि अनुसूचित जाति– जनजातियों के क्रीमी लेयर को आरक्षण के लाभ से वंचित कर देना चाहिए। अब रिटायरमेंट से कुछ ही रोज पहले उन्होंने अपनी ये राय दोहराई है। प्रधान न्यायाधीश के जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा है कि अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण के लाभ से क्रीमी लेयर को वंचित कर दिया जाना चाहिए। ये मांग पुरानी है, लेकिन अब यह दलील भारत के प्रधान न्यायाधीश ने दी है, जो खुद अनुसूचित जाति से आते हैं। इसलिए इस कथन का खास महत्त्व है। एक सेमीनार में जस्टिस गवई ने कहा– श्आरक्षण की सुविधा देते समय आईएएस अधिकारी के बाल–बच्चों को गरीब खेतिहर मजदूर की संतान के साथ समान धरातल पर नहीं रखा जा सकता। अतरू जो सिद्धांत ओबीसी के मामले में लागू किया गया, उसे अनुसूचित जातियों के मामले में भी किया जाना चाहिए। पिछले साल दिए एक निर्णय में जस्टिस गवई ने कहा था कि राज्यों को अनुसूचित जाति– जनजातियों में क्रीमी लेयर की पहचान की नीति बनानी चाहिए और इन तबकों को आरक्षण के लाभ से वंचित कर देना चाहिए। अब प्रधान न्यायाधीश पद से रिटायरमेंट से कुछ ही रोज पहले उन्होंने अपनी ये राय एक सार्वजनिक भाषण में दोहराई है। आरक्षण समर्थक कुछ समूहों की तरफ से इस पर तीखी प्रतिक्रिया होगी, जैसाकि उपरोक्त न्यायिक निर्णय के समय हुआ था। कहा जाएगा कि आरक्षण गरीबी हटाने का जरिया नहीं, बल्कि यह निर्णय के सर्वोच्च स्तरों पर प्रतिनिधित्व का माध्यम है। इसलिए इसमें कोई आर्थिक पैमाना नहीं शामिल किया जा सकता। लेकिन आरक्षण नीति की अब तक जो यात्रा है, उसमें यह तर्क कमजोर पड़ चुका है। ओबीसी आरक्षण शैक्षिक एवं सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया गया। इसी तर्क पर ओबीसी जातियों के बीच श्रेणियां बनाई गईं। अब अनुसूचित जातियों के मामले में भी इस तर्क पर न्यायिक मुहर लग चुकी है। फिर 2019 में जब आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों के लिए 10 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था हुई, तो वह विशुद्ध रूप से आर्थिक पैमाने पर था। आरक्षण से गरीबी और पिछड़ापन मिट सकते हैं या नहीं, यह दीगर मुद्दा है। लेकिन आरक्षण पर पिछले 35 वर्षों में जो सियासत आगे बढ़ी है, उसके बीच यह प्रश्न पहले ही बहस से बाहर हो चुका है– शायद इसलिए कि यह आज किसी का मकसद ही नहीं है!

जी-20 शिखर सम्मेलन में नरेंद्र मोदी के सुझावों की रोशनी

ललित

जी–20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन सत्र इस बार जिस गंभीर मुद्दे पर केन्द्रित रहा, वह दुनिया के सामने उभरते खतरों की बदलती प्रकृति को स्पष्ट करता है। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के साथ–साथ ड्रग तस्करी को भी वैश्विक शांति, सुरक्षा और मानव अस्तित्व के लिए उतना ही घातक बताया जितना किसी संगठित हिंसा को माना जाता है। उनकी यह चेतावनी केवल कूटनीतिक वक्तव्य नहीं बल्कि बढ़ती वैश्विक वास्तविकताओं का सटीक विश्लेषण है। यह तथ्य अब निर्विवाद है कि मादक पदार्थों की तस्करी आतंकवाद को ईंधन प्रदान करने वाला सबसे बड़ा स्त्रोत बन चुकी है। अरबों डॉलर का यह अवैध व्यापार केवल अपराध जगत को नहीं बल्कि राष्ट्रों की सुरक्षा, समाज की स्थिरता और युवाओं के भविष्य को भी चूर–चूर कर रहा है। मोदी ने अपने संबोधन में साफ कहा कि दुनिया के बड़े राष्ट्रों को ड्रग–माफिया और उसके आतंकवाद से जुड़े वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ एकजुट होकर निर्णायक लड़ाई लड़नी होगी। दुनिया आज जिस गति से नए–नए मादक पदार्थों के जाल में फंसती जा रही है, वह वैश्विक चिंता और भी बढ़ाता है। फेंटानाइल जैसे अत्यंत खतरनाक सिंथेटिक ड्रग्स ने अमेरिका में स्वास्थ्य–संकट की भयावह स्थिति पैदा कर दी है, जहां प्रतिदिन अनेक लोग इसके कारण जान गंवा रहे हैं। यह संकट किसी एक देश की समस्या नहीं, बल्कि मानव जीवन पर मंडरा रहा एक वैश्विक खतरा है। यह मानना भूल होगी कि ऐसे ड्रग्स केवल एक महाद्वीप तक सीमित रह सकते हैंय संगठित तस्करी के नेटवर्क इसकी पहुंच दुनिया के किसी भी कोने तक ले जा सकते हैं। यही कारण है कि मोदी ने चेताया कि यदि अभी निर्णायक कार्रवाई नहीं हुई, तो यह त्रासदी अन्य देशों में भी फैल सकती है। ड्रग्स माफिया केवल एक आपराधिक व्यापार नहीं, बल्कि मानव समाज की जड़ों को खोखला करने वाला वैश्विक संकट है। नशे का कारोबार सीमाओं, कानूनों और नैतिक मूल्यों–तीनों को धत्ता बताकर फैल रहा है। यह न केवल युवाओं के भविष्य को निगल रहा है, बल्कि देशों की आंतरिक सुरक्षा, सामाजिक स्थिरता और आर्थिक व्यवस्था को भी कमजोर कर रहा है। इसलिए ड्रग्स माफिया का खतरा अब केवल कानून–व्यवस्था का विषय नहीं, बल्कि मानव सभ्यता के अस्तित्व का प्रश्न बन गया है। दुनिया भर में नशे का अवैध व्यापार एक विशाल संगठित नेटवर्क के रूप में विकसित हो चुका है, जिसमें माफिया, कार्टेल, हथियार गिरोह, आतंकवादी संगठन और भ्रष्ट तंत्र की गहरी सांठगांठ शामिल है। यह नेटवर्क इतना शक्तिशाली है कि कई देशों में यह समानान्तर सत्ता जैसा व्यवहार करता है। अफगानिस्तान, मैक्सिको, कोलंबिया, म्यांमार, नाइजीरिया, रूस और यूरोप तथा एशिया के अनेक हिस्सों में ड्रग्स कार्टेलों ने शासन प्रणालियों को चुनौती दी है। अनेक जगह तो स्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि सरकारें या तो इस लड़ाई में कमजोर पड़ जाती हैं या फिर समझौते करने को मजबूर हो जाती हैं। मोदी ने इस पर नियंत्रण के लिये दुनिया को एकजुट होने की आवश्यकता व्यक्त की। जी–20 देशों की यह जिम्मेदारी बनती है कि वे ड्रग्स के अवैध उत्पादन, वितरण, ऑनलाइन डार्क–नेट व्यापार, क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से होने वाले भुगतान और सीमा–पार तस्करी पर न केवल नियंत्रण करें बल्कि इसके खिलाफ साझा रणनीति भी अपनाएं। मोदी ने इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए–प्रत्येक देश में अवैध वित्तीय गतिविधियों पर कड़ा नियंत्रण, एआई के दुरुपयोग को रोकने के लिए सामूहिक प्रयास, डेटा साझाकरण को बढ़ावा, तकनीकी सहयोग को सुदृढ़ करना तथा डिजिटल और साइबर अपराधों के विरुद्ध नई वैश्विक नीति बनाना। एआई का दुरुपयोग आज केवल गलत सूचना फैलाने या साइबर अपराध तक सीमित नहीं रहाय उसके माध्यम से ड्रग्स की ऑनलाइन बिक्री, नकली पहचान, एन्क्रिप्टेड चौनल और तस्करों के गुप्त नेटवर्क को चलाने में भी व्यापक उपयोग होने लगा है। इस पर रोक अब सामूहिक प्रयासों के बिना संभव नहीं। इस वर्ष का जी–20 शिखर सम्मेलन अमेरिका की अनुपस्थिति के बावजूद काफी सफल माना गया। यह सफलता केवल उपस्थिति की संख्या में नहीं बल्कि चर्चाओं की गुणवत्ता, मुद्दों की गंभीरता और लिए गए निर्णयों के ठोस स्वरूप में दिखाई दी। बड़े देशों का एक–दूसरे से समन्वय और वैश्विक चुनौतियों को लेकर स्पष्टता इस सम्मेलन की बड़ी उपलब्धि रही। दुनिया का बदलता भू–राजनीतिक वातावरण, यूक्रेन और मध्य–पूर्व जैसे संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितताएं और ग्लोबल साउथ की महत्वाकांक्षाएं–इन सबके बीच भी यह सम्मेलन शांत, रचनात्मक और समाधान–उन्मुख रहा। यह संकेत है कि दुनिया के राष्ट्र अब प्रतिस्पर्धा से ज्यादा सहयोग को प्राथमिकता देने लगे हैं। ड्रग–तस्करी और आतंकवाद जैसे मुद्दे किसी भी देश की सीमाओं में बंधे नहीं रह सकतेय इसलिए उनका समाधान भी सीमाओं के पार सहयोग से ही संभव है। मोदी के सुझावों का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि भारत लंबे समय से सीमा–पार आतंकवाद का शिकार रहा है और दक्षिण एशिया में ड्रग–तस्करी का एक बड़ा ट्रांजिट–पॉइंट भी बनता रहा है। भारत ने तकनीक, कानून और कूटनीति–तीनों स्तरों पर इस खतरे से मुकाबला करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिनसे दुनिया सीख सकती है। भारत का अनुभव बताता है कि ड्रग–नेटवर्क को समाप्त करने के लिए तीन मोर्चों पर काम करना अत्यंत आवश्यक है–कड़ी सीमा निगरानी, सोशल–मीडिया एवं एआई आधारित निगरानी तंत्र को मजबूत करना, और युवाओं में नशामुक्ति एवं जागरूकता को बढ़ाना। केवल कानून पर्याप्त नहींय सामाजिक–मानसिक जागरूकता भी उतनी ही जरूरी है। जी–20 सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सक्रिय, प्रभावशाली और केंद्रीय उपस्थिति ने एक बार फिर सिद्ध किया कि वे आज वैश्विक परिदृश्य के सबसे सशक्त, निर्णायक और भरोसेमंद नेताओं में अग्रणी हैं। अमेरिका की अनुपस्थिति के बावजूद विश्व मंच पर नेतृत्व का जो शून्य बन सकता था, उसे मोदी ने अपने संयमित, दूरदर्शी और कूटनीतिक करिश्मे से भर दिया। ड्रग–तस्करी, आतंकवाद, एआई के दुरुपयोग, वैश्विक अर्थव्यवस्था, ग्लोबल साउथ और मानव–कल्याण जैसे विविध मुद्दों पर उनकी स्पष्ट दृष्टि और व्यावहारिक समाधान ने दुनिया को यह विश्वास दिलाया कि भारत न केवल उभरती शक्ति है बल्कि स्थिर और सकारात्मक दिशा दिखाने वाला पथ–प्रदर्शक भी है। उनकी उपस्थिति ने यह भी रेखांकित किया कि बदलती वैश्विक राजनीति में जहां कई राष्ट्र आंतरिक संघर्षों और नीतिगत अनिश्चितताओं से जूझ रहे हैं, वहीं भारत एक विश्वसनीय, स्थिर और दूरदर्शी नेतृत्व प्रस्तुत कर रहा है। मोदी का यह उभार केवल भारत की प्रतिष्ठा को ऊंचा नहीं उठाता बल्कि दुनिया को एक ऐसे नेतृत्व का विकल्प देता है जो विकास, शांति, सुरक्षा और वैश्विक सहयोग के नए मॉडल को आगे बढ़ा सकता है और यही आज की दुनिया के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की "एकात्म मानववाद" के दर्शनशास्त्र को वैश्विक विकास के भविष्य में महत्वपूर्ण बताते हुए दुनिया से इसे अपनाने की अपील की। मोदी ने पारंपरिक ज्ञान, स्वास्थ्य क्षेत्र, क्रिटिकल मिनरल्स, सैटेलाइट डेटा एक्सेस, अफ्रीका में क्षमता निर्माण और ड्रग–टेरर नेटवर्क के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। उनका कहना था कि इससे दीर्घकालिक शांति, मजबूती और सतत विकास सुनिश्चित होगा। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के अध्यक्षता की प्रशंसा की, जिसने कौशल आधारित प्रवासन, पर्यटन, खाद्य सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल अर्थव्यवस्था, नवाचार और महिलाओं के सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। उन्होंने यह भी बताया कि नई दिल्ली जी–20 शिखर सम्मेलन में लिए गए कई ऐतिहासिक निर्णयों पर आगे कार्य हो रहा है। जी–20 शिखर सम्मेलन का संकेत स्पष्ट हैः दुनिया अब नए खतरे पहचान रही है और उन पर सामूहिक कार्रवाई के लिए तैयार भी हो रही है। आतंकवाद और ड्रग–तस्करी के गहरे रिश्ते को तोड़ना वैश्विक शांति के लिए अनिवार्य है। यदि आर्थिक, स्वास्थ्य और सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित समाज बनाना है, तो ड्रग–पर नियंत्रण करना ही होगा। दुनिया की बढ़ती असुरक्षा का मुकाबला केवल हथियारों से नहीं, बल्कि जागरूकता, संयम, शिक्षा और संवेदनशीलता से होगा। जब तक हम नशे के इस वैश्विक खतरे को एक सामूहिक लड़ाई न मानें, तब तक सुरक्षा केवल एक भ्रम बनी रहेगी।

आत्मनिर्भर भारत के लिए श्रम सुधार

डॉ. मनसुख

कई दशकों तक भारत कमजोर आर्थिक विकास, गहरे भ्रष्टाचार और रोजगार सृजन व श्रमिक कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता के अभाव से जूझता रहा। राजनीतिक उद्देश्यों से होने वाले घेराव और बंदी ने बार–बार औद्योगिक गतिविधियों को बाधित किया, निवेश को रोका और व्यवस्था में विश्वास को कम किया। यह दुख की बात है कि पिछली सरकारों ने श्रमिक कल्याण को केवल नारों तक सीमित कर दिया और श्रमिकों के वास्तविक मुद्दों को गंभीरता से लेने में विफल रहीं। इस जड़ता को तोड़ने के लिए देश के नेतृत्व में एक बड़ा बदलाव जरूरी था। लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्श्रमेव जयतेय का आह्वान किया और कहा कि भारत की विकास यात्रा के केंद्र में श्रम की गरिमा यानी मजदूरों का सम्मान होना चाहिए। यह केवल एक नारा नहीं था, बल्कि एक नई राष्ट्रीय सोच की शुरुआत थी, जिसमें नीतियां बनाते समय श्रमिकों को केंद्र में रखा गया। ऐसे बदलाव की जरूरत बहुत समय से महसूस की जा रही थी। भारत के ज्यादातर श्रम कानून 1920 से 1950 के बीच बने थे और उनमें औपनिवेशिक सोच की झलक रहती थी। दूसरी ओर, दुनिया में काम करने का तरीका पूरी तरह बदल चुका था। गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था का बढ़ना, डिजिटल कामकाज, लचीली कार्य संरचनाएं और नए प्रकार के उद्यम तेजी से उभर रहे थे। लेकिन भारत के पुराने श्रम कानून समय के साथ नहीं बदले, और आधुनिक कार्यबल या प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे थे। एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पंच प्रण के माध्यम से यह संदेश दिया कि हमें औपनिवेशिक मानसिकता छोड़कर भविष्य की जरूरतों के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। पुराने कानून इसलिए नहीं बने रहे क्योंकि वे अच्छे थे, बल्कि इसलिए क्योंकि पिछली सरकारों में उन्हें बदलने का राजनीतिक साहस, इच्छा शक्ति और दूरदृष्टि की कमी थी। बदलती परिस्थितियों और देश की जरूरतों के अनुसार उन्हें आधुनिक बनाने की हिम्मत किसी ने नहीं दिखाई। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, भारत का वैश्विक कद अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। दुनिया मानती है कि भारत अब भविष्य को आकार देने में केवल भाग नहीं ले रहा है, बल्कि उसे परिभाषित करने में भी मदद कर रहा है। लेकिन इस ऐतिहासिक क्षण का सही अर्थों में लाभ उठाने और संभावनाओं को दीर्घकालिक समृद्धि में बदलने के लिए, भारत औपनिवेशिक काल के उस श्रम ढांचे से बंधा नहीं रह सकता जो सशक्तिकरण के बजाय नियंत्रण के लिए बनाया गया था। इसलिए, बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन, औपचारिकता का विस्तार और सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक बदलाव आवश्यक था। इस राष्ट्रीय आवश्यकता को समझते हुए, मोदी सरकार ने स्वतंत्र भारत के सबसे महत्वपूर्ण सुधारों में से एक को लागू किया। पहले के 29 बिखरे हुए श्रम कानूनों को मिलाकर चार सरल और स्पष्ट श्रम संहिताएं बनाई गईं रू वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता और व व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता। 21 नवंबर 2025 को ये श्रम संहिताएं लागू हो गईं। ये संहिताएं मिलकर एक आधुनिक श्रम ढांचा स्थापित करती हैं, जो श्रमिक–समर्थक और विकास–समर्थक दोनों है, और यह दिखाता है कि भारत अब तेजी से बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था की मांगों को पूरा करने के लिए तैयार है। संसद द्वारा 2019 और 2020 में श्रम संहिताओं को पारित किया गया था, कई राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, श्रमिक संघों और उद्योग निकायों ने उनके प्रगतिशील इरादे का स्वागत किया है। उनकी खूबियों को पहचानते हुए, सभी राजनीतिक दलों के राज्यों ने संहिताओं के अनुसार से अपने श्रम कानूनों में बदलाव किए। उदाहरण के लिए, जिन राज्यों ने महिलाओं को उनकी सहमति और पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ रात में काम करने की अनुमति दी है, वहाँ कुल महिला रोजगार में 13 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। सभी क्षेत्रों के स्टेकहोल्डर्स ने एक पुरानी हो चुकी श्रम प्रणाली से आगे बढ़ने की आवश्यकता को पहचाना है। उनके योगदान ने एक संतुलित ढाँचा तैयार करने में मदद की है जो श्रमिकों की सुरक्षा करता है और साथ ही अर्थव्यवस्था को विकसित होने में भी सक्षम बनाता है। श्रमिकों और इंडस्ट्री लीडर्स के साथ मेरी बातचीत में जो बात हमेशा सामने आई है वह कार्यस्थल पर स्पष्टता, निष्पक्षता और सम्मान की आवश्यकता पर बल देती है। इसी मार्गदर्शक सिद्धांत ने हमारे सुधारों को आकार दिया है, जिसने एक जटिल और बिखरे हुए सिस्टम को एक ऐसे सिस्टम से बदल दिया है जो सरल, पारदर्शी और हर श्रमिक की सुरक्षा करने वाला है। श्रम संहिताएं अपने मूलभाव और अक्षरशरू रूप में, नियोक्ताओं की अपेक्षाओं को संतुलित करते हुए श्रमिकों के हितों को प्राथमिकता देती हैं। वे निवारक स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देती हैं और सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करती हैं। ये संहिताएं ऑडियो–विजुअल श्रमिकों और गिग तथा प्लेटफॉर्म श्रमिकों को औपचारिक मान्यता प्रदान करती हैं।

अर्बन नक्सल अब खुलकर सामने आने लगे, इंडिया गेट पर प्रदर्शन में जो हुआ उसने गहरी चिंता पैदा की

दिल्ली में रविवार को हुए प्रदूषण–विरोधी प्रदर्शनों का उद्देश्य जितना वैध था, उसकी परिणति उतनी ही दुर्भाग्यपूर्ण। राजधानी की हवा विषैली हो चुकी है, नागरिकों का आक्रोश स्वाभाविक है और सरकारों से कड़े कदमों की अपेक्षा भी पूरी तरह जायज। परन्तु जिस प्रकार यह प्रदर्शन हिंसक हुआ, मिर्च–स्प्रे का उपयोग किया गया, पुलिसकर्मियों को चोट पहुँचाई गई और सबसे गंभीर बात कि एक माओवादी कमांडर हिडमा के पोस्टर लहराए गए, वह न केवल कानून–व्यवस्था के लिए चुनौती है बल्कि सजग लोकतांत्रिक नागरिकता की मूल भावना पर प्रहार भी है। प्रदूषण पर चिंता जताने का लोकतांत्रिक अधिकार और नक्सलवाद का प्रचार दो बिल्कुल अलग चीजें हैं, जिन्हें किसी भी परिस्थिति में एक–दूसरे से मिलाया नहीं जा सकता। हिडमा जैसा व्यक्ति, जो दशकों तक सुरक्षा बलों के लिए घातक रहा, अनेक निर्दोष ग्रामीणों की मौत का कारण बना और हिंसा की राजनीति को बढ़ावा देता रहा, यदि उसके पोस्टर राजधानी की सड़कों पर लहराए जाते हैं, तो यह लोकतंत्र का गंभीर उपहास है। चाहे यह किसी "छोटी टुकड़ी" का कृत्य रहा हो या किसी सुनियोजित समूह का, यह कृत्य किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। सबसे पहले निंदा उस हिंसा की होनी चाहिए जो प्रदर्शनकारियों ने अपनाई। मिर्च–स्प्रे का इस्तेमाल, बैरिकेड तोड़ना, सड़क अवरोध, एम्बुलेंस जैसे आपात वाहनों को रोकना, ये सब लोकतांत्रिक विरोध के दायरे में आते ही नहीं। संविधान ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है, पर यह स्वतंत्रता दूसरों की सुरक्षा और अधिकारों को चोट पहुँचाने की अनुमति नहीं देती। पुलिसकर्मी भी इंसान हैं, वह रोज नागरिकों की सुरक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उन पर इस तरह हमला पूरी तरह निंदनीय है। दूसरी ओर, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि सत्ता पक्ष इस पूरे घटनाक्रम को केवल "अर्बन नक्सल" कथा तक सीमित कर राहत की साँस न ले। प्रदूषण वास्तव में एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल बन चुका है। दिल्ली–छब्द की हवा ऐसी है कि सुबह की सैर अब स्वास्थ्य के लिए उपयोगी नहीं, बल्कि नुकसानदायक हो चुकी है। हर साल सरकारें समितियाँ बनाती हैं, घोषणाएँ करती हैं, परंतु जमीनी बदलाव नहीं दिखते। आम आदमी का गुस्सा इसलिए फूटता है क्योंकि उसे नीतिगत निष्क्रियता साफ दिखाई देती है। और यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि गुस्से का अर्थ यह नहीं कि किसी भी चरमपंथी विचारधारा को मंच मिल जाए। एक लोकतंत्र में गलत नीतियों की आलोचना की जा सकती है, परंतु लोकतंत्र विरोधी हिंसक संगठनों की प्रशंसा नहीं की जा सकती। यह विरोध की सीमा नहीं, बल्कि उसकी आत्मा को ही दूषित कर देता है। घटना का तीसरा पहलू इससे भी चिंताजनक कि हर बार की तरह यह मुद्दा भी राजनीतिक बयानबाजी की भेंट चढ़ गया। जरूरी बात यह है कि सभी दल मिलकर प्रदूषण जैसे गंभीर संकट पर कदम उठाएँ। छब्द के राज्यों के बीच समन्वय, निर्माण–धूल नियंत्रण, पराली प्रबंधन, सार्वजनिक परिवहन का विस्तार, ये सब आज ही करने की जरूरत है। जनता सड़क पर इसलिए उतरती है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी आवाज संस्थानों तक पहुँच नहीं पा रही है। लेकिन यदि जनता में से भी कुछ लोग लोकतांत्रिक ढाँचे को ध्वस्त करने वाले तत्वों की तरफ झुक जाएँ, तो यह समाज की सामूहिक विफलता है। इसलिए, इस पूरी घटना की घोर निंदा आवश्यक हैकृ न केवल इसलिए कि हिंसा हुई, बल्कि इसलिए भी कि लोकतांत्रिक विरोध की पवित्रता भंग हुई। प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई को किसी भी प्रकार की अतिवादी राजनीति से मुक्त रखना होगा। हिडमा जैसे चरमपंथियों के पोस्टर राजधानी की सड़कों पर स्वीकार्य नहीं हो सकते। यह हमारे लोकतंत्र की संवेदनशीलता पर आघात है और इससे सख्ती से निपटना ही होगा। बहरहाल, सरकारों को प्रदूषण पर ठोस और त्वरित कदम उठाने चाहिए ताकि ऐसे प्रदर्शन भटक कर हिंसा और अतिवाद का रूप न लें। नागरिकों का आक्रोश तभी सही दिशा में जा सकता है, जब राज्य व्यवस्था उसे सुनने और समाधान देने को तैयार हो। परंतु लोकतंत्र में कोई भी लक्ष्य हिंसा, भय और चरमपंथ के सहारे नहीं प्राप्त किया जा सकता। यह समान रूप से नागरिक, सरकार और समाज, सभी की साझा जिम्मेदारी है कि विरोध भी हो, पर सभ्य, शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप।

दक्षिण एशियाई देशों के लिए सावधानी और सहयोग से चलने का समय

डॉ. अरुण

अब समय आ गया है कि हम कुछ सकारात्मक सोचना शुरू करें। हमें यह समझना होगा कि हम तीन न्यूक्लियर हथियार वाले पड़ोसी हैं। बयानबाजी करने के बजाय हमें अपने पड़ोसियों के साथ भरोसा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। यह आसान काम नहीं होगा क्योंकि अमेरिकी भारत–प्रशांत मामलों में ज्यादा से ज्यादा शामिल हो रहे हैं। उनका गेम प्लान इस इलाके में हथियार बेचना है। पिछले कु छ समय से दक्षिण एशिया में एक के बाद एक तेजी से हो रही घटनाएं चिंता की बात हैं। हमने 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादी हिंसा देखी, जिसमें 26 बेगुनाह लोग मारे गए। अब 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किले के पास एक कार में हुए धमाके में 15 लोग मारे गए हैं। उसी दिन इस्लामाबाद में हुए ध माके में 10 लोग मारे गए। यह इस बात का इशारा है कि आतंकवादी जब चाहें कहीं भी लोगों को मार सकते हैं। इन घटनाओं ने इस इलाके में सुरक्षा की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अंदरूनी सुरक्षा संकट से बाहरी तनाव पैदा हो सकता है, और भारत और पाकिस्तान भी एक–दूसरे पर इल्जाम लगाने में देर नहीं लगाते। इन घटनाओं से तनाव बढ़ता है और बयानबाजी बढ़ती है, जिससे हथियारों की होड़ बढ़ जाती है। ऐसी घटनाओं से बाहरी ताकतों को भी फायदा उठाने का मौका मिलता है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 60 से ज्यादा बार यह दावा दोहराया है कि उन्होंने इस साल भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को श्खत्म करनेश में मदद कीय उन्होंने भारत और पाकिस्तान को ध मकी दी कि अगर उन्होंने झगड़ा खत्म नहीं किया तो वे 350प्रतिशत टैरिफ लगा देंगेय श्मोदी, शरीफ ने मुझे फोन कियाश। श्मैं नहीं चाहता कि आप लोग एक–दूसरे पर न्यूक्लियर हथियार चलाओ, लाखों लोगों को मारो और लॉस एंजिल्स में न्यूक्लियर धूल उड़ेश। उन्होंने आगे दावा किया कि उन्हें श्प्रध ानमंत्री मोदी का फोन आया, जिसमें कहा गया, श्हमारा काम हो गयाश। मैंने कहा, श्तुम्हारा क्या हो गया?श मिस्टर ट्रंप ने कहा और दावा किया कि मिस्टर मोदी ने जवाब दियारू श्हम जंग नहीं करने जा रहे हैं।श ट्रंप का धमकी भरे अंदाज में कहना एक तरह से दो आजाद देशों के आपसी मामलों में सीधा दखल है। हैरानी की बात है कि भारत सरकार ने इनकार का कोई बयान जारी नहीं किया है। अमेरिका–चीन इकानॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन की नई रिपोर्ट में भारत के साथ मई 2025 की लड़ाई में पाकिस्तान की मिलिट्री कामयाबी का दावा किया गया है, और पहलगाम को श्विद्रोही हमलाश बताया गया है। रिपोर्ट में चीन के लॉजिस्टिक्स के साथ पाकिस्तान को अप्रत्यक्ष समर्थन पर भी जोर दिया गया है। कोई हैरानी नहीं कि मिस्टर ट्रंप ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल मुनीर को लंच पर बुलाया। वे आर्थिक रूप से मुश्किल में फंसे पाकिस्तान के साथ रिश्ते बढ़ाने के लिए भी तैयार हैं। एक और घटना जो हुई है, वह है बांग्लादेश की एक अदालत द्वारा तत्कालीन प्रध ानमंत्री हसीना वाजेद को मौत की सजा सुनाना। हसीना वाजेद अभी भारत में हैं और बांग्लादेश सरकार ने मांग की है कि उन्हें ढाका वापस भेजा जाए। भारत सरकार के लिए यह कोई आसान फैसला नहीं है। हसीना शेख मुजीब–उर–रहमान की बेटी हैं, जिन्होंने पाकिस्तान से बांग्लादेश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। इतिहास गवाह है कि 1970–71 में पाकिस्तानी मिलिट्री ने कितने जुल्म किए थे। 2015 में ढाका की अपनी यात्रा के दौरान मुझे पता चला कि पाकिस्तानी सेना ने उस समय यूनिवर्सिटी, कॉलेज और मेडिकल संस्थानों में पढ़े–लिखे लोगों पर खास ध्यान देते हुए करीब 30 लाख लोगों को मार डाला। भारत सरकार ने लोगों के विद्रोह में मदद की और आखिरकार पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया और बांग्लादेश बना। तब से भारत के बांग्लादेश के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं। इस दौरान बांग्लादेश ने आर्थिक रूप से तरक्की की और स्वास्थ्य समेत कई क्षेत्रों में भारत के विकास के संकेतकों को पीछे छोड़ दिया। फिर भी देश में बेरोजगारी और महंगाई जैसी कई समस्याएं थीं। इसकी वजह से छात्रों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए। हसीना वाजेद स्थिति की गंभीरता को समझने में नाकाम रहीं। छात्रों से बात करने के बजाय उन्होंने बहुत ज्यादा दमन का सहारा लिया, जिससे बड़ी संख्या में छात्र मारे गए। इससे इस्लामिक कट्टरपंथी गुटों को जगह मिली। अब यह पूरी तरह साफ है कि यह सब तब हुआ जब उन्होंने अमेरिका को एक द्वीप देने से मना कर दिया था। उन्होंने साजिश रची और स्थिति का पूरा फायदा उठाया और मोहम्मद यूनुस को केयर टेकर बना दिया। इस तरह अब भारत के पूर्वी और पश्चिमी दोनों बॉर्डर पर तनाव है। चीन के साथ हमारे व्यापारिक संबंध हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच कई बैठकों के बावजूद इस बात की कम ही संभावना है यह रिश्ता रणनीतिगत बन पाएगा। हसीना वाजेद के प्रत्यार्पण के बारे में सरकार को सभी राजनीतिक पार्टियों को बुलाकर उनसे बातचीत करनी चाहिए। यह उकसाने या कट्टर होने का समय नहीं है क्योंकि इस इलाके में कोई भी बड़ी सशस्त्र लड़ाई बहुत बुरी होगी। यह दुख की बात है कि अमेरिका के साथ रिश्ते बनाने के चक्कर में हमने नॉन–अलाइंड मूवमेंट (एनएएम) को छोड़ दिया। हमने सार्क को भी लगभग बेकार कर दिया। इसीलिए ग्लोबल साउथ अब हमारी तरफ नहीं देखता। वे इसके बजाय चीन के साथ मिल रहे हैं। इसलिए अब समय आ गया है कि हम कुछ सकारात्मक सोचना शुरू करें। हमें यह समझना होगा कि हम तीन न्यूक्लियर हथियार वाले पड़ोसी हैं। बयानबाजी करने के बजाय हमें अपने पड़ोसियों के साथ भरोसा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। यह आसान काम नहीं होगा क्योंकि अमेरिकी भारत–प्रशांत मामलों में ज्यादा से ज्यादा शामिल हो रहे हैं। उनका गेम प्लान इस इलाके में हथियार बेचना है परन्तु हथियारों की रेस नहीं बढ़ने देना चाहिए, क्योंकि यह इलाके की सुरक्षा और विकास के लिए नुकसानदायक होगा। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरी सामाजिक जरूरतों को लिए आवश्यक संसाधन हथियारों की दौड़ में लग जाएंगे।

एक हाथ में तिरंगा तो दूसरे में भगवा ध्वज लेकर निकले मोदी, राम दरबार में झुकाया शीश

लखनऊ, (संवाददाता)। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण के जरिए 'संकल्प सिद्धि' के लिए रामनगरी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। जयश्रीराम, जय जय हनुमान के गगनभेदी नारों संग अयोध्यावासियों ने प्रधानमंत्री के काफिले पर पुष्पवर्षा भी की। श्रीराम की अयोध्या ने प्रधानमंत्री का पूरे रास्ते में अभूतपूर्व स्वागत किया। अयोध्यावासियों के एक हाथ में भगवा ध्वज तो दूसरे हाथ में तिरंगा फहरा रहा था। वहीं स्वागत से अभिभूत प्रधानमंत्री ने भी हाथ हिलाकर अयोध्यावासियों का अभिवादन किया। अयोध्या पहुंचने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार सुबह अयोध्या पहुंचे। साकेत महाविद्यालय पर उनका हेलीकॉप्टर उतरा। वहां से काफिले संग टेढ़ी बाजार होते हुए उन्होंने श्रीराम मंदिर परिसर में प्रवेश किया। इस दौरान अयोध्यावासियों ने जयश्रीराम, जय जय हनुमान के गगनभेदी नारों संग उनका स्वागत किया। अयोध्यावासी एक हाथ में भगवा ध्वज तो दूसरे हाथ में तिरंगा फहराते हुए प्रधानमंत्री का स्वागत करते रहे। प्रधानमंत्री ने भी पूरे रास्ते में हाथ हिलाकर अयोध्यावासियों का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सप्त मंदिर में भी पूजा–अर्चना की। मंदिर परिसर में महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, महर्षि वाल्मीकि, देवी अहिल्या, निषादराज गुह्य और माता शबरी मंदिर में पहुंचकर प्रधानमंत्री ने शीश झुकाया। प्रधानमंत्री ने शेषावतार मंदिर व माता अन्नपूर्णा मंदिर में भी दर्शन–पूजन किया। प्रधानमंत्री अयोध्या में साकेत विश्वविद्यालय हैलीपेड पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर की तरफ प्रस्थान किया। श्री राम मंदिर परिसर में राम दरबार पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक डॉ. मोहन भागवत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दर्शन–पूजन व आरती की। यहां पुजारियों ने तीनों विशिष्टजनों को राम नामी गमछा ओढ़ाया व प्रसाद दिया।

सच्चा प्रेम देता है त्याग का संदेश : किरीट भाई

लखनऊ, (संवाददाता)। बीरबल साहनी मार्ग स्थित श्री श्याम मंदिर में चल रही सात दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा के तीसरे दिन कथावाचक किरीट भाई ने प्रेम, त्याग और धर्म के वास्तविक स्वरूप पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण ने संसार को प्रेम का पाठ पढ़ाया और सिखाया कि सच्चा प्रेम व्यक्ति को लालच और स्वार्थ से दूर करता है। आज प्रेम के नाम पर भावनाओं से खेलना सबसे बड़ा अपराध है, जिसे भगवान कभी क्षमा नहीं करते। सोमवार को कथा का शुभारंभ दोपहर तीन बजे भक्त प्रह्लाद और नृसिंह अवतार के प्रसंग से हुआ। किरीट भाई ने कहा कि धर्म का मार्ग सदा शांति का होता है, जबकि अधर्म का क्षणिक सुख कई जन्मों का कष्ट देता है। उन्होंने कहा कि निस्वार्थ प्रेम मनुष्य को ईश्वर के निकट ले जाता है और भागवत की एक–एक कथा आत्मा को शांति प्रदान करती है। कार्यक्रम में मुख्य यजमान अतुल अग्रवाल, सुनीता अग्रवाल, महामंत्री रूपेश अग्रवाल, कोषाध्यक्ष आशीष अग्रवाल, एसीपी महानगर अंकित कुमार, एसएचओ अखिलेश मिश्रा, अनुराग साहू और पंकज सहित कई श्रद्धालु उपस्थित रहे। अंधविश्वास से बचने का संदेश राजाजीपुरम में जलालपुर क्रॉसिंग पारा मार्ग के पास चल रही सात दिवसीय श्रीरामकथा के दूसरे दिन कथावाचक राघवचरणानुरागी हरिओम तिवारी ने अंधविश्वास के कुप्रभावों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि विश्वास के साथ विवेक का होना भी आवश्यक है, क्योंकि विवेक छोड़ने पर विश्वास अंधविश्वास बन जाता है और जीवन में कष्ट लाता है। सोमवार की कथा में सती चरित्र और शिव–पार्वती विवाह का विस्तृत वर्णन किया गया।

संक्षिप्त खबरें

भौतिक सुख नहीं अपनाएं धर्म की राह

लखनऊ, (संवाददाता)। नई जेल रोड स्थित धरमावत खेड़ा में चल रही सात दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा के चौथे दिन सोमवार को श्रीकृष्ण जन्म का प्रसंग सुनाया गया। कथावाचक दिनेशानंद मृदुल ने कहा कि भौतिक सुख के लिए कुछ लोग अधर्म की राह पर चल पड़ते हैं। कथा के जरिये सही मार्ग पर चलने का संदेश दिया। कहा कि जब–जब धर्म की हानि होती है प्रभु अवतार लेते हैं। मोहनलालगंज बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र जायसवाल, महामंत्री रामलखन यादव, दिलेश कुमार सिंह, शिवप्रताप सिंह, मनोज सिंह व सिंटू सिंह मौजूद रहे।

जब सोने की चिड़िया खोजने निकला बच्चा

लखनऊ, (संवाददाता)। बाल सुलभ मन को आज भी दादी–नानी के जमाने की कहानियां आकर्षित करती हैं। लोक संस्कृति शोध संस्थान ऐसे ही आयोजनों के जरिये बच्चों के मन को टटोल रहा है और उनमें नैतिकता, संवेदनशीलता और कल्पनाशीलता का विकास किया जा रहा है। मासिक शृंखला दादीदृनानी की कहानी का 75वां आयोजन सोमवार को पल्टन छावनी स्थित बाल निकुंज स्कूल में किया गया। स्टोरीमैन जीतेश श्रीवास्तव ने बच्चों को सोने की चिड़िया और नीली बकरी की प्रेरक कहानी सुनाकर जीवन मूल्यों, लक्ष्य के प्रति एकाग्रता और साहस का संदेश दिया। स्कूल के प्रबंध निदेशक एचएन जायसवाल, प्रधानाचार्य रश्मि शुक्ला आदि मौजूद रहे।

खुद को बुलंद करने के लिए पढ़ना जरूरी

लखनऊ, (संवाददाता)। मीरा शाह वेलफेयर सोसाइटी की ओर से चिनहट स्थित हजरत सैयद शहीद मीरा शाह बाबा की दरगाह पर सोमवार को नातिया मुकाबला हुआ। स्कूल व मदरसे के विद्यार्थियों ने प्रतिभा दिखाई। 1090 वीमेन क्राइम सेल में एसपी रुचिता चौधरी ने छात्र व छात्राओं से खुद को बुलंद करने के लिए तालीम को जरूरी बताया। दरगाह के मुतवल्ली एवं सज्जादानशीन सैयद मोहम्मद अतीक शाह की अध्यक्षता में प्रतियोगिता हुई। सेवानिवृत्त आईएएस डॉ. अनीस अंसारी, मौलाना सैयद सैफ अब्बास नकवी, दरगाह कमेटी की सचिव डॉ. खुशनुमा अतीक, मो. इमरान खान आदि मौजूद रहे।

विश्व धरोहर सप्ताह पर गोरखपुर के रामपुर नवीन प्राथमिक विद्यालय में चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित

लखनऊ, (संवाददाता)। विश्व धरोहर सप्ताह के अवसर पर सोमवार को प्राथमिक विद्यालय, रामपुर नवीन, गोरखपुर में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में छात्रों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग करते हुए अपनी कल्पनाशीलता और कला कौशल का प्रदर्शन किया।प्रतियोगिता में उज्ज्वल ने प्रथम, साक्षी सिंह ने द्वितीय और रितिका ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा नैन्सी रावत और आरती सिंह को सांत्वना पुरस्कार प्रदान किए गए। सभी प्रतिभागियों को पुरस्कृत कर प्रोत्साहित किया गया।कार्यक्रम में क्षेत्रीय पुरातत्त्व अधिकारी डॉ. कृष्ण मोहन दुबे ने छात्रों को विरासत के महत्व और धरोहर संरक्षण की आवश्यकता के विषय में जानकारी दी।

नालंदा परंपरा का तिब्बत से रहा है आध्यात्मिक संबंध

लखनऊ, (संवाददाता)। लखनऊ विश्वविद्यालय के एपी सेन हॉल में सोमवार को राजनीति विज्ञान विभाग की ओर से ''तिब्बत अवेयरनेस टॉकरू सिक्योरिटी एंड एनवायरनमेंट'' विषय पर विशेष व्याख्यान हुआ। मुख्य वक्ता केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के राष्ट्रपति पेनपा त्सेरिंग ने बताया कि नालंदा परंपरा से तिब्बत का आध्यात्मिक संबंध था। तिब्बती लिपि की उत्पत्ति भारत में हुई थी। उन्होंने तिब्बत की सामरिक स्थिति, पर्यावरणीय संकटों और एशियाई सुरक्षा ढांचे पर व्यापक चर्चा की। उन्होंने कला संकाय के डीन प्रो. अरविंद मोहन ने तिब्बत की ऐतिहासिक–राजनीतिक पृष्ठभूमि पर बात रखी। संस्कृति बोर्ड निदेशक प्रो. अंचल श्रीवास्तव ने तिब्बती संस्कृति संरक्षण पर विचार साझा किए।

गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी पर्व पर गूंजे शबद कीर्तन

लखनऊ, (संवाददाता)। सिखों के नौवें गुरु श्री तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी पर्व के उपलक्ष्य में डीएवी कॉलेज में विशेष समागम का आयोजन किया जा रहा है। सोमवार शाम यहां विशेष दीवान सजाया गया जो देर रात तक रहा। बड़ी संख्या में लोगों ने यहां पहुंचकर माथा टेका। यहियागंज गुरुद्वारा के सचिव मनमोहन सिंह हैप्पी ने बताया कि डॉ. गुरमीत सिंह के संयोजन में सोमवार शाम से देर रात तक शबद कीर्तन गूंजे। इस दौरान लुधियाना से आए दविंदर सिंह सोढ़ी, पटियाला से जसकरन सिंह और श्री दरबार साहब अमृतसर से गुरजिंदर सिंह ने शबद कीर्तन से संगतों को निहाल किया। मंगलवार को सुबह से लेकर देर शाम तक डीएवी कॉलेज में मुख्य आयोजन होगा। सुबह 11 बजे श्री गुरुग्रंथ साहिब पर गुलाब के फूलों की वर्षा की जाएगी। शाम सात बजे से देर रात तक गुरुद्वारा यहियागंज में विशेष आयोजन होगा। एलडीए कॉलोनी कानपुर रोड स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा मानसरोवर में भी आयोजन चल रहे हैं। अध्यक्ष सरदार सम्पूरन सिंह बग्गा ने बताया कि तीन दिवसीय दीवान की शुरुआत 23 नवंबर को अमृत वेले से नितनेम, सुखमनी साहिब जी के पाठ अखंड पाठ से हुई थी। मंगलवार को अखंड पाठ की समाप्ति होगी। सोमवार को हजूरी रागी सुखजीत सिंह ने आशा दी वार के कीर्तन किए। हेड ग्रंथी ज्ञानी परमजीत सिंह ने संगत को गुरु तेग बहादुर साहिब जी के जीवन और बलिदान के बारे में बताया। मंगलवार को शहीदी पर्व के अवसर पर विशेष दीवान सुबह नौ से दोपहर 12 बजे तक सजेगा और गुरु का लंगर वितरित किया जाएगा। महासचिव चरणजीत सिंह, सचिव गगनदीप सिंह बग्गा, कोषाध्यक्ष परमजीत चंदर, गुरमीत सिंह, अमरज्योत सिंह, सतनाम सेठी, सुरिंदर बग्गा, इकबाल सिंह आदि मौजूद रहे।

अयोध्या की गली–गली में गूंज रही राम धुन, उल्लास में डूबे श्रद्धालु चरम पर आध्यात्मिक माहौल

लखनऊ, (संवाददाता)। स्थित राम मंदिर के ध्वजारोहण समारोह के दौरान रामपथ, भक्तिपथ, धर्मपथ और जन्मभूमि पथ समेत अन्य मार्गों और गलियों में राम धुन गूंज रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की खुशी में श्रद्धालु उल्लासित हैं। हर कोई भूमि पूजन और प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब राम मंदिर के ध्वजारोहण समारोह को लेकर आस्था के भाव से सराबोर है। बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु सरयू स्नान कर मंदिरों में दर्शन पूजन कर रहे हैं। इस मौके पर सुरक्षा चाक चौबंद है। एसपीजी, एनएसजी और एटीएस सड़कों और गलियों में मुस्तैद हैं। ध्वजारोहण और पीएम मोदी के आगमन के मौके पर अयोध्या को नई दुल्हन की तरह सजाया गया है। चौक चौराहे फूलों से सजे हैं। भव्यता ऐसी है कि त्रेता युग जैसा आभास हो रहा है। राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण की शुभ सुबह अयोध्या पूरी तरह आस्था की रौ में डूबी नजर आई। पीएम मोदी के आगमन को लेकर शहर कई क्षेत्रों को सील भी किया गया है। लेकिन, इन पाबंदियों के बावजूद श्रद्धालुओं के आस्था के कदम थमे नहीं। बड़ी संख्या में भक्त सरयू घाट पहुंचे। स्नान–दान के साथ ध्यान कर दिन की पवित्र शुरुआत की। कई श्रद्धालुओं ने गो–दान कर पुण्य अर्जित किया। शहर के मंदिरों में घंटा–घड़ियाल लगातार गूंज रहे हैं। भले ही सुरक्षा कारणों से रामलला के दर्शन आज संभव नहीं हो पा रहे, लेकिन अयोध्या के अन्य मंदिरों में रोजमर्रा की तरह पूजा–अर्चना निर्बाध जारी है। पूरे शहर में आध्यात्मिक माहौल चरम पर है। श्रद्धालुओं का उत्साह दर्शाता है कि आस्था किसी भी बंदिश से बड़ी होती है। ध्वजारोहण के इस अवसर पर अयोध्या पूर्ण रूप से भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर है।

संक्षिप्त खबरें

अलीगंज के प्राचीन संत रविदास मंदिर में 4.64 करोड़ की पर्यटन विकास योजना शुरू

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग राजधानी लखनऊ में धार्मिक पर्यटन को नई दिशा देने के उद्देश्य से धार्मिक स्थलों के समग्र विकास पर तेजी से काम कर रहा है। इसी क्रम में अलीगंज स्थित प्राचीन संत रविदास मंदिर का समेकित पर्यटन विकास 4.64 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के तहत शुरू हो गया है। सौंदर्यीकरण से लेकर आधुनिक पर्यटक सुविधाओं के विस्तार तक पूरे परिसर को नया स्वरूप देने की तैयारी है। यह जानकारी पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने दी।मंत्री ने बताया कि मंदिर में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या और स्थानीय महत्व को देखते हुए सड़कों की मरम्मत, पेयजल व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, श्रद्धालुओं के बैठने हेतु बेंच और परिसर के जर्जर हिस्सों के पुनरुद्धार जैसे कार्य किए जा रहे हैं। उद्देश्य यह है कि भक्तों को सुगम, सुरक्षित और बेहतर अनुभव प्रदान किया जा सके।लीगंज का संत रविदास मंदिर राजधानी के प्राचीन धार्मिक स्थलों में शामिल है। मुख्य द्वार पर अंकित 1924 का स्थापना वर्ष इस मंदिर के 101 वर्ष पुराने इतिहास का प्रमाण है। यह स्थल लंबे समय से स्थानीय समुदाय के धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन का केंद्र रहा है। परिसर में तीन प्राचीन समाधियां भी स्थित हैं, जिनमें से एक मंदिर निर्माण से भी पूर्व की मानी जाती है, जबकि दो समाधियां बाबा लीलादास और बाबा टिकाईदास से संबंधित हैं।मंदिर से स्थानीय लोगों का गहरा भावनात्मक जुड़ाव है। वर्षों से मंदिर के बाहर जूते–चप्पल की मरम्मत का काम करने वाले नौमी लाल बताते हैं कि उनके पिता भी यहीं काम करते थे। मिष्ठान विक्रेता भोलानाथ का कहना है कि उनके बाबा 1931 से यहां दुकान लगाते थे। हर वर्ष संत रविदास जयंती पर यहां बड़े पैमाने पर विशेष आयोजन होता है, जिसमें स्थानीय लोग बढ़–चढ़कर हिस्सा लेते हैं और सजावट में सहयोग करते हैं।स्थनीय व्यापारियों का मानना है ।

उप मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन में फरियादियों की समस्याएं सुनी, संतुष्टिपूर्ण समाधान के निर्देश

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोमवार को लखनऊ कैम्प कार्यालय में आयोजित जनता दर्शन में विभिन्न जिलों से आए सैकड़ों फरियादियों की समस्याएं सुनीं और उन्हें त्वरित व प्रभावी समाधान का भरोसा दिलाया। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक समस्या का संतुष्टिपरक और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, साथ ही संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए।उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि विवाद, उत्पीड़न और अवैध कब्जों से जुड़े मामलों को अत्यधिक गंभीरता से निपटाया जाए और जहां आवश्यकता हो, कठोर कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर अधिकारी मौके पर जाकर निरीक्षण करें।जनता दर्शन में पुरुष, महिलाएं, बुजुर्ग और युवा बड़ी संख्या में पहुंचे थे। अधिकतर शिकायतें भूमि व राजस्व विवाद, चिकित्सा सहायता, पेंशन, आवास, सड़क, बिजली–पानी, शिक्षा, रोजगार और पुलिस कार्रवाई से जुड़े मुद्दों की थीं। उप मुख्यमंत्री ने सभी प्रकरणों को ध्यानपूर्वक सुना और संबंधित अधिकारियों से दूरभाष पर वार्ता कर तत्काल दिशा–निर्देश दिए।उन्होंने कहा कि जनता दर्शन आमजन से सीधे संवाद का माध्यम है, ।

निराश्रित गोवंश की सुरक्षा पर सख्त हुए पशुधन मंत्री, सभी गौशालाओं का एक सप्ताह में निरीक्षण का निर्देश

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश के पशुधन विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने ठंड के मौसम को देखते हुए सभी जिलों के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रदेश की सभी गौशालाओं का एक सप्ताह के भीतर सघन निरीक्षण हर हाल में पूरा कराया जाए। उन्होंने कहा कि निराश्रित गोवंश की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है, इसलिए किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।विधान भवन स्थित कार्यालय में गोआश्रय स्थलों की व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए मंत्री ने कहा कि गौवंश को ठंड से बचाने के लिए तिरपाल, अलाव, भूसा, गर्माहट देने वाली व्यवस्था और अन्य आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि ठंड से किसी भी गोवंश की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। पशुचिकित्साधिकारी नियमित रूप से आश्रय स्थलों पर जाकर स्वास्थ्य परीक्षण, दवाओं और उपचार की व्यवस्था देखें।उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिला स्तर पर नोडल अधिकारी चारा, भूसा, पानी, रोशनी और आश्रय से जुड़ी सभी सुविधाओं की समय–समय पर जांच करें। उपमुख्य पशु चिकित्साधिकारी, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी और मंडल स्तरीय अपर निदेशक प्रतिदिन कम से कम एक गौशाला का अनिवार्य रूप से निरीक्षण करेंगे। मंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि सीवीओ जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी के साथ समन्वय स्थापित कर सभी गौशालाओं का सघन निरीक्षण सुनिश्चित कराएं। किसी भी प्रकार की लापरवाही सामने आने पर जिम्मेदार अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी।पशुधन मंत्री ने कहा कि योगी सरकार निराश्रित गोवंश के संरक्षण और संवर्धन हेतु पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने निर्देश दिए कि गोवंश शेड, पानी पीने की चरहिया, खडंजा आदि मजबूत और व्यवस्थित तरीके से बनाए जाएँ। यदि किसी गौ आश्रय स्थल में अव्यवस्था की शिकायत मिलती है, तो तत्काल सुधार किया जाए तथा निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता न किया जाए।मंत्री ने मंडलवार निरीक्षण भी निर्धारित किए हैं। आजमगढ़अपर निदेशक डॉ. अरविंद कुमारकृमिर्जापुर मंडलसमीक्षा बैठक में विशेष सचिव देवेंद्र पाण्डेय, एमडी पीसीडीएफ वैभव श्रीवास्तव, दुग्ध आयुक्त के. धनलक्ष्मी, विशेष सचिव राम सहाय यादव, निदेशक पशुपालन डॉ. योगेंद्र पवार, संयुक्त निदेशक एलडीबी डॉ. पी.एन. सिंह सहित ।

छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजनाओं के लिए समाज कल्याण विभाग ने जारी की संशोधित समय–सारणी

लखनऊ, (संवाददाता)। समाज कल्याण विभाग ने सत्र 2025–26 के लिए छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनाओं की संशोधित समय–सारणी जारी कर दी है। यह नई समय–सारणी अनुसूचित जाति, जनजाति, सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के उन सभी छात्रों पर लागू होगी, जो कक्षा 09–10 (पूर्वदशम) और कक्षा 11–12 (दशमोत्तर) में अध्ययनरत हैं। नई समय–सीमा के साथ विभाग ने छात्रों, अभिभावकों और विद्यालय प्रशासन से समय पर सभी औपचारिकताएं पूरी करने की अपील की है, ताकि किसी भी पात्र छात्र को लाभ से वंचित न होना पड़े।समाज कल्याण विभाग के उपनिदेशक और योजनाधिकारी आनंद कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों द्वारा मास्टर डेटा लॉक करने की प्रक्रिया 25 नवम्बर से 01 दिसम्बर, 2025 तक संपन्न होगी। इसके बाद 25 नवम्बर से 08 दिसम्बर तक जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा विद्यालयों के डेटा का सत्यापन किया जाएगा।उन्होंने आगे कहा कि कक्षा 09 से 12 तक के छात्रों के ऑनलाइन आवेदन 25 नवम्बर से 6 दिसम्बर, 2025 तक लिए जाएंगे। आवेदन का अंतिम प्रिंट छात्र 7 दिसम्बर तक निकाल सकेंगे। छात्रों को अपने आवेदन की हार्डकॉपी तथा सभी आवश्यक प्रमाण–पत्र 9 दिसम्बर, 2025 तक अपने विद्यालय में जमा करने होंगे।विद्यालय स्तर पर ऑनलाइन सत्यापन 13 दिसम्बर, 2025 तक पूरा किया जाएगा। इसके बाद जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा छात्रों की वास्तविक संख्या का मिलान 15 से 20 दिसम्बर के बीच किया जाएगा। एनआईसी द्वारा डेटा मिलान 15 से 23 दिसम्बर तक होगा, जबकि छात्र–स्तर की त्रुटियों का समाधान 23 से 28 दिसम्बर तक किया जाएगा।जिला स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृति और डेटा की अंतिम लॉकिंग 23 दिसम्बर, 2025 से 31 जनवरी, 2026 तक की जाएगी। निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद छात्रवृत्ति की धनराशि 09 फरवरी, 2026 तक च्ब्डै प्रणाली के माध्यम से सीधे छात्रों के बैंक खातों में भेज दी जाएगी।पनिदेशक आनंद कुमार सिंह ने सभी छात्रों और उनके अभिभावकों से अपील की है कि वे निर्धारित समय–सारणी का पालन करते हुए सभी चरण समय पर पूरा करें, ताकि छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ किसी भी स्तर पर बाधित न हो।

वाराणसी में सड़क निर्माण के चार कार्यों को 52 लाख 11 हजार की मंजूरी

लखनऊ, (संवाददाता)। प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025–26 की त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत वाराणसी में सड़क और नाली निर्माण से जुड़े चार महत्वपूर्ण कार्यों को मंजूरी प्रदान की है। नियोजन विभाग द्वारा जारी शासनादेश की प्रति जिलाधिकारी वाराणसी को भेज दी गई है।जारी आदेश के अनुसार चंदापुर से पटेल बस्ती होते हुए अमरपट्टी तक लेपन और सीसी रोड निर्माण के लिए 16.19 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। ग्राम कुरौली में शारदा सहायक नहर से धन्नू राजभर के घर, परदेशी राजभर के घर से होते हुए स्व. रामसूरत के मकान से बीबीसी के आगे मंडी परिषद रोड तक सीसी रोड निर्माण के लिए 12 लाख रुपये मंजूर हुए हैं। छीतमपुर धौरहरा मार्ग से गोलधमकवा, राजेश चौबे पत्रकार के घर से कउवापुर तक सड़क निर्माण हेतु 12.68 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

जंबूरी में दिखा लघु भारत का अद्भुत रूप

लखनऊ, (संवाददाता)। राजधानी लखनऊ के डिफेंस एक्सपो मैदान में सोमवार को नजारा कुछ अलग ही था। अक्सर वीरान रहने वाला यह क्षेत्र आज देश–विदेश से आए 32 हजार युवाओं की चहल–पहल से न सिर्फ गुलजार था बल्कि झूम रहा था। एक तरफ यूपी के युवा काशी की गंगा आरती कर रहे थे तो दूसरी तरफ पंजाब के युवा भंगड़ा डाल रहे थे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के 19वीं राष्ट्रीय जंबूरी में वजारोहण करते ही अटल स्टेडियम का कोना–कोना जय जंबूरी, जय जंबूरी के नारों से गूंज उठा। राष्ट्रीय गीत वंदेमातरम के साथ आयोजन की शुरुआत हुई तो 350 एकड़ में फैले मैदान में जुटे 32 हजार युवा एकसाथ झूमने लगे। सऊदी अरब, मालद्वीव और नेपाल से पहुंचे युवा भी देशभक्ति गीतों पर थिरक रहे थे। अलग–अलग रंग के परिधानों में जुटे युवा लघु भारत का स्वरूप पेश कर रहे थे। श्श्भारत माता के वीर नहीं कम, बन के हम तूफान चले। एक तिरंगे के पीछे पूरा हिंदुस्तान चले ने समा बांध दिया। सभी युवा अपने–अपने राज्य का नृत्य पेश कर रहे थे। पंजाब की पारंपरिक युद्धकला गतका ने रोमांच भरा तो राजस्थानी घूमर ने मन मोह लिया। श्श्चक दे इंडियाश्श की धुन पर देश–विदेश से आए रोवर–रेंजर थिरक रहे थे। यह सभी एक भारत, श्रेष्ठ भारत के साथ–साथ अनेकता में एकता का संदेश भी दे रहे थे। इसके पहले आयोजन का निरीक्षण करने निकलीं राज्यपाल का युवाओं ने जय जंबूरी–जय जंबूरी नारों से स्वागत किया। जंबूरी का आकर्षण डायमंड जुबली परेड भी रही। राजस्थान ने इसका नेतृत्व किया। इसके पीछे सऊदी अरब, मालदीव, नेपाल स्काउट, श्रीलंका गाल गाइड एसोसिएशन, बॉयज स्काउट एसोसिएशन, भारत स्काउट एंड गाइड यूपी, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, भारतीय रेलवे, चंडीगढ़ यूटी, छत्तीसगढ़, दिल्ली, दादरा नागर हवेली, ईस्ट कोस्ट रेलवे, ईस्ट सेंट्रल रेलवे की टीम ने किया। एक समय पूरे मैदान में सिर्फ कदमों की लयबद्ध ताल ही सुनाई दे रही थी। उद्घाटन समारोह में राष्ट्रीय मुख्यायुक्त डॉ. केके खंडेलवाल ने कहा कि यह गर्व का समय है। युवा सेवा, अनुशासन और नवाचार का मॉडल बनकर हमारे सामने खड़े हैं। आयोजन में ड्रोन शो से जहां शांति, एकता की कहानी लिखी जाएगी। वहीं, हाई रोप गतिविधि युवाओं को बेहतर अनुशासन की मिसाल देगी। जंबूरी परंपरा, मूल्यों और नवाचार को एकदूसरे से जोड़ती है। उन्होंने बेहतर व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया।

खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु आज क्रेताक्र विक्रेता सम्मेलन

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, गोमती नगर, लखनऊ में आयोजित खादी महोत्सव–2025 के अंतर्गत 25 नवम्बर को पूर्वाह्न 11:30 बजे से अपराह्न 01:30 बजे तक क्रेतादृविक्रेता सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन का उद्देश्य प्रदेश की खादी एवं ग्रामोद्योग इकाइयों को बड़े विपणन मंच से जोड़ना तथा उद्यमियों को राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार विस्तार के अवसर प्रदान करना है।प्रदेश सरकार पारंपरिक उद्योगों को वैश्विक पहचान दिलाने और खादी–स्वदेशी उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने हेतु लगातार प्रयासरत है।

भारत के विकास में महिलाओं का योगदान विशेष रहा : रजनी तिवारी

हरदोई(अम्बरीष कुमार सक्सेना) बुधवार को श्री बाबूराम त्रिवेदी सरस्वती शिशु मंदिर अलीपुर हरदोई में सप्तशक्ति संगम कार्यक्रम किया गया।

इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्रीमती रजनी तिवारी जी उच्च शिक्षा राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा भारत के विकास में महिलाओं का योगदान विशेष रहा आदिकाल से आज तक महिलाओं ने चुनौतियों का सामना किया है देश के उत्थान के लिए अपना योगदान दिया हमें अपनी समर्थ को समझना होगा महिलाओं के सामने उचित अवसर है विकसित देश में महिलाओं का योगदान रहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्वयं सहायता समूह आदि महिलाओं के लिए मुहिम चलाई जा रही बेटे बेटियों को संस्कार युक्त शिक्षा दीजिए स्वदेशी अपनाओ तभी आत्मनिर्भर भारत बनेगा।

क्षेत्रीय सप्तशक्ति संगम संयोजिका श्रीमती निधि देवी की नई में समाहित सप्त शक्तियां , कीर्ति श्री स्मृति मेघा गति क्षमता आदि के बारे में विस्तृत जानकारी करते हुए पर्यावरण संरक्षण पांच परिवर्तन की बात कही। हमें अपनी परंपराओं को बनाए रखना है । पशु पक्षियों के प्रति अच्छा भाव रखना है ।भारतीय संस्कृति हमें समन्वय सिखाती है पर्यावरण चेतना विकसित हो इसके लिए हमें प्रयास करना है , हमें अपनी नदियों को साफ एवं स्वच्छ रखना है ऊर्जा की बचत करें यदि हम मात्र शक्तियों सजक हो तो हमारा भारत एक शक्तिशाली देश बन सकता है।राष्ट्र को आगे बढ़ाने में महिलाओं का विशेष योगदान है । कार्यक्रम में विशिष्ट महिलाओं को श्रीमती मंत्री जी द्वारा सम्मानित किया गया श्रीमती सीमा कुमारी जी, श्रीमती अनुराधा मिश्रा, श्रीमती अदिती गौड , श्रीमती कृष्णा रस्तोगी जी, श्रीमती रीता गुप्ता जी। सुश्री मनीषा देवी मिश्रा आदि को सम्मानित किया गया किया । कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही श्रीमती प्रेमाबती जी ने अध्यक्षीय भाषण में महिलाओं को आत्मनिर्भर आत्मश्वास्वत बनाना होगा अंत में बच्चों की झांकियां के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। कार्यक्रम संयोजिका या कार्यक्रम के संचालन के रूप में श्रीमती पूर्णिमा त्रिवेदी ने कुशलता पूर्वक कार्यक्रम का संचालन किया । 43 गांवों की 567 महिलाओ ने कार्यक्रम में सहभागिता की।

अंबेडकर की प्रतिमा का मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने किया अनावरण

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर के जफराबाद थाना क्षेत्र के उत्तरगावा गांव में डॉ भीमराव अंबेडकर की भव्य प्रतिमा का बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने अनावरण फिट काटकर किया। अनावरण में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कहा कि डॉ भीमराव अंबेडकर सिर्फ संविधान निर्माता ही नही बल्कि सामाजिक बराबरी शिक्षा और मानवाधिकारों के अद्वितीय प्रतीक थे।उन्होंने अपने विचारों से सभी को जागरूक किया।मंत्री ने अंबेडकर जी की भव्य प्रतिमा को स्थापित करने के लिए सहयोगी सदस्यों की सराहना की। इस अवसर पर नंदलाल यादव, कमला यादव, जितेंद्र कुमार, विवेक रंजन यादव, अजय कुमार, संजय कुमार, अरविंद कुमार, नंदलाल यादव, ज्ञान प्रकाश, राज कुमार, शमशेर, ऋषिकेश आदि मौजूद रहे।

संक्षिप्त खबरें

पीड़ित का बयान दर्ज, जांच में अभी नहीं मिली कोई गड़बड़ी

गोरखपुर, (संवाददाता)। फर्जी कॉल के जरिये एंबुलेंस दौड़ाने के मामले में जांच टीम ने पीड़ित का बयान दर्ज कर लिया है। जांच भी लगभग पूरी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि जांच के दौरान अभी तक कोई गड़बड़ी नहीं मिली है। सीएमओ का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी रहेगी। हालांकि पीड़ित पक्ष का कहना है कि उसके पास पूरे साक्ष्य हैं, जिसके बारे में जांच टीम को जानकारी दी गई है। संतकबीरनगर जिले के बभनौली गांव निवासी सौरभ मिश्रा 108 एंबुलेंस में ईएमटी के पद पर पाली ठर्रापार में तैनात थे। विगत दिनों उन्होंने अपनी कंपनी के वरिष्ठ अफसर पर गंभीर आरोप लगाए थे। सौरभ का आरोप था कि वरिष्ठ अफसर फर्जी कॉल कर केस बनाने के लिए कहते हैं। रोजाना 200 से 300 किलोमीटर एंबुलेंस चलाने का दबाव बनाते हैं। इन्कार पर नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है। सीएमओ ने भी अपने स्तर से मामले की जांच की। टीम ने पीड़ित का बयान भी दर्ज किया। बताया जा रहा है कि टीम को अभी कोई गड़बड़ी नहीं मिली है। कोई ठोस साक्ष्य भी नहीं उपलब्ध हो सके हैं। इधर, पीड़ित का कहना है कि उसके पास पर्याप्त सबूत हैं, जिससे बयान दर्ज कराने के दौरान टीम को बताया गया था।

भुगतान न होने से धीमी हुई जल जीवन मिशन योजना की रफ्तार

भदोही, (संवाददाता)। हर घर जल योजना में कराए गए कार्यों का भुगतान न होने से योजना की रफ्तार धीमी हो गई है। लगभग 285 करोड़ का भुगतान लटकने से कई स्थानों पर कार्यदायी संस्थाएं और ठेकेदार काम करने से कतरा रहे हैं क्योंकि वह वर्करों को उनकी मजदूरी नहीं दे पा रहे हैं। जिले में कुल 4293 करोड़ रुपये की लागत से 1459 पेयजल परियोजनाएं स्वीकृत हैं। इन पेयजल परियोजनाओं से चयनित 3818 राजस्व गांवों में नल से जल पहुंचाना है। इसमें पाइप लाइन बिछाने, घर–घर नल कनेक्शन देने के काम लगभग पूरे हो चुके हैं। अब ओवरहेड टैंकों के बनाने पर जोर है लेकिन पिछले डेढ़ सालों से शासन स्तर पर भुगतान लटकने से कार्य धीमा हो गया है। महराजगंज, तरवा, रानी की सराय, पल्हनी, पवई, बिलरियागंज, मेंहनगर, लालगंज, सठियांव, पल्हना आदि ब्लॉकों के कई गांवों में पैसे के अभाव में सबसे ज्यादा परियोजनाएं लंबित हैं।

सत्यापन में लापरवाही पड़ी भारी, दो सचिवों को नोटिस जारी

भदोही, (संवाददाता)। जिले में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान में सोमवार को भी बूथों पर मतदाताओं को गणना प्रपत्र दिया गया। गांव से लेकर नगर तक हेल्प डेस्क में लोगों को प्रपत्र वितरित किया गया। बेहतर कार्य करने वाले तीन बीएलओ को जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। वहीं डुप्लीकेट मतदाता सूची के सत्यापन में लापरवाही बरतने पर दो सचिवों को नोटिस जारी किया गया। सोमवार को भी ज्ञानपुर, गोपीगंज, भदोही, नई बाजार नगर निकायों के हेल्प डेस्क पर बीएलओ लोगों को गणना प्रपत्र वितरित कर उसके भरने के बारे में जानकारी दी।

हवा ने पकड़ी रफ्तार, ठिठुरन से नहीं मिल रही निजात

भदोही, (संवाददाता)। जिले में सोमवार को 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ हवा चली। इससे ठंड ने रफ्तार पकड़ ली है। शाम होते ही गलन की साथ लोग ठिठुरन को विवश हैं। इन दिनों ठंड से तनिक भी राहत नहीं मिल रही है। यह मौसम सेहत के लिए नुकसानदेय है। जरा सी लापरवाही बरतने पर भी लोग बीमार पड़ रहे हैं। जिला अस्पताल की ओपीडी 836 रही। सोमवार को दिन भर धूप खिली रही, लोगों ने धूप का आंनद लिया। रविवार को पछुआ हवा सात किमी के रफ्तार से चल रही थी, जबकि सोमवार को 12 किमी के रफ्तार से चलने लगी। इसके कारण गलन का अहसास हुआ। ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव के पास बैठे, लेकिन राहत नहीं मिली।

60 विद्यालय नहीं बन सकेंगे परीक्षा केंद्र

भदोही, (संवाददाता)। जिले के 60 वित्तविहीन विद्यालय बोर्ड परीक्षा में केंद्र नहीं बन सकेंगे। डीएम की गठित टीम के सत्यापन में ये विद्यालय बोर्ड के तय मानक को पूर्ण करने में फेल हो गए हैं। किसी में चहारदीवारी नहीं है तो किसी में पर्याप्त संख्या में कक्ष, शौचालय और फर्नीचर का अभाव है। सोमवार को 110 विद्यालयों की सत्यापन रिपोर्ट परिषद की वेबसाइट पर विभागीय स्तर से अपलोड कर दिया गया। 30 नवंबर तक परिषद आनलाइन केंद्रो का निर्धारण करेगा। जिले में तीन राजकीय इंटर कॉलेज सहित 38 राजकीय विद्यालय, 25 वित्तपोषित समेत कुल 193 माध्यमिक विद्यालय संचालित हो रहे हैं। इसमें हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा में करीब 55 हजार छात्र–छात्राएं पंजीकृत हैं। परीक्षा की तिथि तय हो चुकी है। 10 नवंबर तक स्कूलों ने केंद्र बनने के लिए आनलाइन आवेदन किया। स्कूलों के भौतिक सत्यापन के लिए तीनों तहसीलों में एसडीएम की अध्यक्षता में डीएम ने टीम गठित किया। 23 नवंबर तक टीम ने करीब 193 विद्यालयों का सत्यापन किया। इसमें 33 राजकीय स्कूल पहले ही बाहर हो चुके थे। अब 60 वित्तविहीन विद्यालय भी परिषद के मानक में फेल हो गए हैं। इसमें सबसे अधिक भदोही तहसील क्षेत्र के विद्यालय शामिल हैं। भदोही में कुल 72 विद्यालयों में 39 में जरूरी सुविधाओं का अभाव रहा। इसी तरह ज्ञानपुर तहसील में 80 में 15 और औराई में 45 में सात विद्यालय मानक पूर्ण नहीं करते मिले। जिला विद्यालय निरीक्षक अंशुमान ने बताया कि 33 राजकीय के साथ ही 60 निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में जरूरी सुविधाएं नहीं है, जिससे इनको केंद्र बनना मुश्किल है।

मेले से जुड़े सभी कार्य 15 दिसंबर तक करवाएं पूरा, बिजली के इन कामों को समय से करवाएं पूरा

गोरखपुर, (संवाददाता)। कमिश्नर अनिल ढींगरा ने सोमवार को गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले खिचड़ी मेले की तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने विभिन्न विभागों को निर्देश दिया कि मेले से जुड़े सभी कार्य 15 दिसंबर तक पूर्ण कर लिए जाएं। उन्होंने मेले में आग से सुरक्षा के विशेष इंतजाम करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खिचड़ी का मेला इस क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला होता है जिसको लेकर पार्किंग व्यवस्था, अलाव एवं सुरक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मेला क्षेत्र की निगरानी सीसीटीवी से भी करायी जाए इसके साथ ही पुलिस भी जगह–जगह तैनात रहे। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में महिला पुलिस की तैनाती की जाए। नगर निगम की ओर से अस्थायी शौचालय की पर्याप्त व्यवस्था रहे। चिकित्सा विभाग अस्थायी अस्पताल के साथ जगह–जगह पर एंबुलेंस तैनात रखे। विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि विभिन्न स्टालों की ओर से प्रयोग की जा रही विद्युत वायरिंग की भी जांच कर लें जिससे कोई घटना न होने पाए। उन्होंने निर्देश दिया कि नालियों को कवर किया जाये। इस अवसर पर जिलाधिकारी दीपक मीणा, डीआईजी एस चन्नपा,एसएसपी राजकरन नैयर सहित विभिन्न अधिकारी उपस्थित रहे।

संक्षिप्त खबरें

पीलीभीत–गोरखपुर एक्सप्रेस का इज्जतनगर तक विस्तार फिलहाल निरस्त

पीलीभीत, (एजेंसी)। रेलवे ने गोरखपुर–पीलीभीत–गोरखपुर एक्सप्रेस का इज्जतनगर तक होने वाला विस्तार फिलहाल निरस्त कर दिया है। सोशल मीडिया के जरिये यह खबर मिलते ही लोगों में मायूसी छा गई। रेलवे ने ट्रेन नंबर 15009/15010 गोरखपुर–पीलीभीत–गोरखपुर का विस्तार इज्जतनगर तक करने की अधिसूचना जारी करने के साथ ही समय सारिणी भी जारी कर दी थी। अधिसूचना के मुताबिक गोरखपुर–पीलीभीत एक्सप्रेस 24 नवंबर की रात गोरखपुर से चलकर 25 को 12रू45 इज्जतनगर तक जाती और उसी दिन ट्रेन नंबर 15010 बनकर इज्जतनगर से अपरान्ह 15:10 बजे वापस गोरखपुर रवाना हो जाती। जोनल मुख्यालय गोरखपुर से रविवार की रात 11रू20 बजे जारी पत्र के जरिए इस ट्रेन के इज्जतनगर तक विस्तार का निरस्तीकरण आदेश जारी किया गया। रेलवे के सूत्रों के मुताबिक आपाधापी में इस ट्रेन के इज्जतनगर तक विस्तार की अधिसूचना तो जारी कर दी गई, लेकिन इसके संचालन में समय सारिणी और क्रू (चालक दल) को लेकर समस्या आ रही है। इसी से इसका इज्जतनगर तक विस्तार फिलहाल निरस्त कर दिया गया है। ये समस्या दूर करने के बाद शायद दोबारा इसके विस्तार का आदेश जारी हो। व्यापारियों में मायूसी मेन मार्केट मैलानी के जनरल स्टोरी व्यवसायी अमित मुखर्जी ने आमान परिवर्तन के काफी समय बाद एक ट्रेन के इज्जतनगर (बरेली) जाने की खबर से लोगों में खुशी हुई थी, लेकिन विस्तार से पहले ही इसके विस्तार को ग्रहण लग गया। ट्रेन का इज्जतनगर तक विस्तार निरस्त होने की खबर मिलते ही लोगों में मायूसी छा गई। मैलानी के फुटवियर विक्रेता सनव्वर अली ने कहा कि बरेली तक ट्रेनें न जाने से बरेली थोक मंडी जाना बहुत मुश्किल और खर्चीला है। गोरखपुर–पीलीभीत एक्सप्रेस का इज्जतनगर तक विस्तार सुनकर बेहद खुशी हुई थी। बरेली तक पहुंचना आसान हो जाता, लेकिन रेलवे ने विस्तार से पहले ही इस ट्रेन का इज्जतनगर तक विस्तार निरस्त कर दिया, जिससे ट्रेन से बरेली तक पहुंचने की उम्मीदें टूट गईं।

वृद्ध की गिरवी जमीन का धोखाधड़ी कर कराया बैनामा

पीलीभीत, (एजेंसी)। सीमावर्ती गांव महाराजपुर के 75 वर्षीय अनुसूचित जाति के किसान के साथ धोखाधड़ी कर उसकी दो एकड़ जमीन हड़पने का गंभीर आरोप सामने आया है। पीड़ित ने डीएम को प्रार्थनापत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। गांव महाराजपुर निवासी बाबूराम ने डीएम को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि रमनगरा में उसकी दो एकड़ पट्टा भूमिधर की जमीन है। घरेलू परिस्थितियों के चलते उसने यह जमीन 30 जून 2021 को रमनगरा निवासी एक व्यक्ति के हाथों 50 हजार रुपये में पांच वर्षों के लिए गिरवी रखी थी। तय हुआ था कि अवधि पूरी होने पर रुपये लौटाकर और खड़ी फसल काटने के बाद वह जमीन वापस ले लेगा। आरोप है कि कुछ समय बाद आरोपी पक्ष ने मिलीभगत कर धोखाधड़ी से जमीन का बैनामा अपने नाम करवा लिया। बाबूराम का कहना है कि गन्ने की फसल की सट्टा पर्ची बनवाने के नाम पर उसे तहसील ले जाकर कागजों पर अंगूठा लगवा लिया।

घर में काटा जा रहा था पड़वा, पुलिस ने मारा छापा, एक गिरफ्तार

सीतापुर, (संवाददाता)। शहर में पशुओं को अवैध रूप से काटने वालों के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने सोमवार को कार्रवाई की। घर पर पड़वा काटने पर छापा मारकर एक आरोपी को गिरफ्तार 60 किलो मांस बरामद किया। पुलिस ने मामले में कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। इसके साथ ही लाइसेंसधारी दुकानों की भी जांच की है। कोहना चौकी प्रभारी यज्ञपाल की ओर से लिखाई गई प्राथमिकी के अनुसार वह कोतवाली में पशु क्रूरता अधिनियम के तहत दर्ज एफआईआर के आरोपी अब्दुल खालिक की तलाश कर रहे थे। सोमवार सुबह मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी का घर शहर के जोगीटोला में है। इस पर पुलिस टीम आरोपी के घर पहुंची तो उसके घर से खटपट की आवाज सुनाई दी। घर का मुख्य द्वार बंद था। पुलिस टीम ने झांककर देखा तो पाया कि घर के आंगन में कुछ लोग एक पड़वे को काट रहे थे। पुलिस टीम दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंची तो अन्य आरोपी जीने के रास्ते से भाग निकले, जबकि मुख्य आरोपी अब्दुल खालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने सिर आदि अवशेषों को देखकर मांस पड़वे का होने की पुष्टि की। मौके से चाकू आदि औजार भी बरामद हुए। पुलिस टीम ने मांस का कुछ हिस्सा सैंपल के लिए भेजते हुए अन्य मांस को दफन करा दिया। इस कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी कराई गई। वहीं, उपकरणों को सील कर दिया गया। शहर कोतवाल अनूप शुक्ला ने बताया कि कई दिनों से पुराने सीतापुर में पशुओं के अवैध कटान की सूचना थी। अमर उजाला ने भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। उस समय कार्रवाई करते हुए इस पर रोक लगाई थी। सोमवार को मुखबिर की सूचना पर फिर कार्रवाई की गई और आरोपियों को पशु का अवैध कटान करते पाया गया। मामले में कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मौके से भागे तीन अन्य आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस ने पुराने सीतापुर में स्थित लाइसेंस की दुकानों पर भी चेकिंग की है। पुलिस सूत्रों के अनुसार पशुओं का अवैध कटान संगठित अपराध की श्रेणी में आता है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर शहर कोतवाली पुलिस ने बीएनएस 111 के तहत एफआईआर दर्ज की है। सीतापुर में बीएनएस 111 के तहत दर्ज यह पहला मामला है। बीएनएस 111 भारतीय न्याय संहिता, 2023 की एक धारा है, जो संगठित अपराध से संबंधित है। यह धारा संगठित अपराधों जैसे अपहरण, डकैती, तस्करी, और जबरन वसूली को परिभाषित करती है। इसके तहत संगठित अपराधों में शामिल व्यक्तियों के लिए कठोर दंड का प्रावधान है। पशु खबर प्रकाशित की थी। इसके बाद करीब एक सप्ताह तक इस संगठित अपराध पर खबरों का प्रकाशन हुआ था। मामला मुख्यमंत्री दरबार में भी पहुंचा था। उस समय शहर कोतवाली पुलिस ने इस पर अंकुश लगाया था। इसके बाद से पुलिस लगातार इस तरह की गतिविधियों पर नजर रख रही थी। इसी क्रम में पुलिस को यह सफलता मिली है।

चार प्रमुख पॉइंट से 41 पुलिस कर्मियों ने डायवर्ट कराए वाहन

सीतापुर, (संवाददाता)। अयोध्या के श्रीराम मंदिर में 25 नवंबर को ध्वाजारोहण को देखते हुए जिले में रूट डायवर्जन लागू किया गया है। सोमवार को चार प्रमुख स्थानों से वाहनों को परिवर्तित मार्गों पर भेजा गया। चारों स्थानों पर 41 पुलिसकर्मियों को लगाया गया है। पहला डायवर्जन महोली से बड़ागांव की तरफ किया गया। यहां दो शिफ्टों में 12 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। बाईपास पुल के नीचे व पुल के ऊपर ड्यूटी लगाई गई। दूसरा डायवर्जन सिधौली में हुआ। यहां पर छह पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। बिसवां क्रासिंग चौराहे से डायवर्जन किया गया है। बिसवां में 11 पुलिसकर्मियों को बड़ा चौराहा पर तैनात किया गया। महमूदाबाद में रामकुंडा चौराहा और बिसवां तिराहा पर 12 लोगों की ड्यूटी तैनात की गई। यातायात निरीक्षक फरीद अहमद ने बताया कि अलग–अलग थानों की ओर से पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। 23 नवंबर की रात 11 बजे से 26 नवंबर सुबह छह बजे तक भारी वाहनों के लिए, वहीं हल्के वाहनों के लिए 24 नवंबर की शाम छह बजे 25 नवंबर की शाम छह बजे तक डायवर्जन लागू रहेगा। महोली से सीतापुर जिलामुख्यालय होकर लखनऊ जाने वाले वाहनों को बड़ागांव, काजीकमालपुर, हरगांव, बिसवां, रेउसा से होते हुए चहलारी घाट की तरफ भेजा गया। सिधौली से लखनऊ होकर बाराबंकी जाने वाले वाहनों को सिधौली के बिसवां चौराहा से बड़ा चौराहा की तरफ मोड़ा गया। जो कि बिसवां, रेउसा चहलारी घाट होते गुजारे गए। बिसवां से हुआ यहां महमूदाबाद से बाराबंकी जाने वाले वाहनों को रेउसा चहलारी घाट होते हुए गुजरा गया। महमूदाबाद से बाराबंकी होते हुए अयोध्या जाने वाले वाहन महमूदाबाद से बिसवां, रेउसा, चहलारी घाट होते हुए भेजे गए।

लाल निशान का विरोध, डीएम को सौंपा पत्र

सीतापुर, (संवाददाता)। शहर में अतिक्रमण हटाने के लिए लाल निशान लगाए गए हैं। इन निशानों को लेकर सोमवार को स्थानीय निवासी भाजपा नेता के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचे। वहां डीएम से मुलाकात की। करीब एक घंटे तक चली बातचीत के दौरान लोगों ने डीएम से कहा कि ये निशान पुराने कब्जेदारों को नजरअंदाज करते हुए लगाए गए हैं। डीएम डॉ. राजा गणपति ने आर ने आश्वासन दिया कि किसी का भी नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के साथ बैठक कर उचित निर्णय लिया जाएगा। लोक निर्माण विभाग व सीतापुर नगर पालिका के अधिकारियों ने वैदेही वाटिका से कांशीराम कॉलोनी तक दोनों तरफ अतिक्रमण हटाने के लिए लाल निशान लगाए हैं। सोमवार से वैदेही वाटिका से अतिक्रमण भी चलना था, लेकिन नगर पालिका और पीडब्लूडी विभाग द्वारा लगाए गए लाल निशान के खिलाफ स्थानीय निवासी लामबंद हो गए। रविवार को भी लोगों ने भाजपा नेता सागर गुप्ता के साथ नगर विकास राज्यमंत्री से मुलाकात की थी। मंत्री के आश्वासन के बाद सोमवार को भाजपा नेता के साथ स्थानीय निवासी कलेक्ट्रेट पहुंचे। वहीं, व्यापारियों ने भी कलेक्ट्रेट में हंगामा किया। इसके बाद सभी लोगों ने डीएम से मिलकर प्रार्थना पत्र सौंपा। स्थानीय निवासियों और व्यापारियों ने बताया कि कांशीराम कॉलोनी तक सड़क के दोनों ओर 33 मीटर तक लाल निशान लगे हैं। इसमें सड़क पर एक भी दुकान नहीं बचेगी।

फ्लाईओवर के पिलरों से देवताओं के चित्र हटेंगे

भदोही, (संवाददाता)। गोपीगंज नगर पालिका परिषद कार्यालय में सोमवार को चेयरमैन जितेंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में बोर्ड की बैठक हुई। इसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। ठंड में सभी वार्डों में पांच–पांच क्विंटल लकड़ी देने का निर्णय लिया गया। साथ ही फ्लाईओवर के पिलरों से देवी देवताओं के चित्र हटाकर उनका उपयोग व्यापारियों के प्रतिष्ठानों के प्रचार–प्रसार के लिए करने का निर्णय लिया गया। हर वार्ड में बेहतर पेयजल सुविधा एवं प्रकाश पर भी जोर दिया गया। सभासदों ने आगामी ठंड के मौसम को देखते हुए नगर के 25 वार्डों में से प्रत्येक में पांच क्विंटल लकड़ी की मांग सभासदों ने की। बोर्ड ने चिह्नित स्थानों पर पालिकाकर्मियों के द्वारा अलाव जलाने का प्रस्ताव पारित किया। सभासद डॉ. आनंद कुमार गुप्ता ने नगर के राजमार्ग ओवरब्रिज के नीचे बनाए गए पिलरों पर से देवी–देवताओं के चित्रों को हटाकर उन्हें नगर के व्यापारियों के प्रतिष्ठानों का प्रचार–प्रसार के लिए उपलब्ध कराने की मांग की।

कदीर पहलवान ने लगाई धोबी पछाड़, चित हुए शेरा

सीतापुर, (संवाददाता)। कार्तिक पूर्णिमा मेला महोत्सव में चल रहे दंगल में सोमवार को छह मुकाबले आयोजित किए गए। इनमें दो कुश्तियां बराबरी पर रहीं। पहलवानों ने अपने प्रतिद्वंद्वी को पटखनी देने के लिए खूब जोर आजमाइश की। पहलवानों के दांव–पेंच देख दर्शक रोमांचित नजर आए। अखाड़े में कुश्ती के दौरान दर्शक तालियां बजाकर पहलवानों का उत्साह बढ़ाते रहे। पहली कुश्ती बरेली के शेरा पहलवान और जम्मू के कदीर पहलवान के बीच हुई, इसमें कदीर पहलवान ने शेरा को धोबी पछाड़ दांव लगाकर चित करते हुए जीत हासिल की। दूसरी कुश्ती कलियर शरीफ के मोनिष पहलवान और दिल्ली के पलटा पहलवान के बीच हुई, इसमें पलटा पहलवान को कई पटखनी देकर मोनिष पहलवान ने जीत दर्ज की। तीसरी कुश्ती झारखंड के पुष्पा पहलवान व सहारनपुर के वकार पहलवान के मध्य कराई गई, इसमें वकार पहलवान विजयी रहे। चौथी कुश्ती जम्मू के कदीर पहलवान और हस्तिनापुर के बल्लू पहलवान के बीच हुई, यह मुकाबला बराबरी पर छूटा। ।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक

श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 – 7007415808, 9415034002

Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबंधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।